RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

# माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-06, अंक-13 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 21 दिसम्बर 2023 पृष्ठ-8, मूल्य-5 रुपए


**सुविचार**

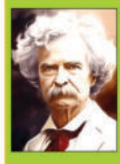

बुनियादी तोर पर दो तरह के लोग होते है जो लोग चीजें हासिल करते है और जो लोग चीजें हासिल करने का दावा करते है, पहले समूह में कम भीड़ होती है।

मार्क टवे्न

# राज्य सरकारें अलर्ट रहें और राजनीति को दूर रखें - मनसुख मंडाविया

**केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक**

**नई दिल्ली।**

देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य से अपील की कि राजनीति को साइड में रखते हुए हमें मिलकर काम करना होगा, साथ ही सतर्क रहने की जरूरत है। अस्पतालों की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल, निगरानी और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बहुत जरूरी है। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ने केरल के बाद महाराष्ट्र और गोवा में भी दस्तक दे दी है। इन दोनों राज्यों में इस नए वेरिएंट जेएन.1 के 19 केस सामने आए हैं। इसके अलावा नौ दिनों में कोरोना केसों में जबरदस्त उछाल आया है। केस दोगुना हो गए हैं।

भारत में कोरोना केस एक बार फिर चिंता पैदा करने लगे हैं। 11 दिसंबर को कोरोना के 938 मामले सामने आए थे। कोरोना मामले 19 दिसंबर को बढ़कर एक हजार 937 तक पहुंच गए। 9 दिनों में कोरोना के मामले दोगुना हो गए हैं। उधर, केरल के बाद अब महाराष्ट्र और गोवा में भी कोरोना के नए वेरिएंट जेएन.1 की पुष्टि हुई है। गोवा में 18 मामले हाल ही में संपन्न हुए फिल्म महोत्सव के दौरान शामिल होने वाले लोगों के हैं। जबकि महाराष्ट्र में एक मामला गोवा सीमा से मिला है। अब तीन राज्यों में नए वेरिएंट की दस्तक से केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में कहा कि, यह सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बार साथ आएं और मिलकर काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि हेल्थ पॉलिटिक्स नहीं है, इसलिए इसे दूर रखना ही समझदारी होगा। हम सभी को अलर्ट पर रहने की जरूरत है। लेकिन घबराकर नहीं साहसिक ढंग से कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल, बढ़ती निगरानी और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि, आइए हम हर तीन महीने में एक बार सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करें। मैं राज्यों को केंद्र की ओर से हरसंभव समर्थन का आश्वासन देता हूं।

### राज्यों को केंद्र की सलाह

कोविड-19 मामलों में हालिया उछाल और केरल के बाद महाराष्ट्र और गोवा में भी जेएन.1 संक्रमण की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कहा है कि अस्पतालों की लगातार निगरानी बहुत जरूरी है। साथ ही टेसि्ंटग पर भी जोर दिया। एडवाइजरी में कहा गया है, आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों को हवा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। क्योंकि श्वसन बीमारी से पीड़ित लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा काफी ज्यादा है।

### राज्यों से टेसि्ंटग बढ़ाने को कहा

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों को कोरोना को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेसि्ंटग की सलाह दी है। साथ ही संक्रमण की रिपोर्ट हर दिन भेजने के भी निर्देश दिए ताकि नए वेरिएंट के प्रभाव का सही आकलन किया जा सके।

# दलित होने की वजह से मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता- कांग्रेस अध्यक्ष

**नई दिल्ली।** कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, जाति को हर मुद्दे में नहीं घसीटा जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही यह सवाल भी किया कि, क्या उन्हें हर बार राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर यह कहना चाहिए कि दलित होने के कारण ऐसा हुआ है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में उनकी, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा नकल उतारे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च सदन में कहा कि संसद परिसर में उनकी नकल उतारकर किसान समाज और उनकी जाति (जाट) का अपमान किया गया है।

खरगे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि, सभापति का काम दूसरे सदस्यों को संरक्षण देना है लेकिन वह खुद इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे अक्सर राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्या मुझे यह कहना चाहिए कि मैं दलित हूं... इसलिए... उन्हें जाति के नाम पर बोल कर लोगों को नहीं भड़काना चाहिए।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि, यह देश के लिए बहुत दुखद दिन है जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी जातियों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह मुद्दा उठाकर संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पूछा कि, क्या अब हर किसी को अपनी जाति बताने वाला ठप्पा लगा कर घूमना चाहिए...? खरगे ने सवाल किया कि, संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में कुछ भी नहीं कहा लेकिन संसद के बाहर उन्होंने अपनी बात रखी तो क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए। संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा करने पर दोनों सदनों से 90 से अधिक विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने के विरोध में विपक्ष के सांसदों ने कल मंगलवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और सदन की 'मॉक कार्यवाही' का आयोजन किया था।

# इंडिया अलायंस की मीटिंग के अगले ही दिन आप की दरार

**नई दिल्ली।** दिल्ली में 'इंडिया' अलायंस की मंगलवार को मीटिंग हुई थी और यह सहमति बनी थी कि इसी महीने के आखिर तक सीट शेयरिंग पर सहमति बना ली जाएगी। लेकिन अगले ही दिन बुधवार को पंजाब में इसके उलट अलगाव की स्थिति बनती दिखाई दी। यहां सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का कहना है कि, वह सभी 13 सीटों पर अकेले ही लड़ेगी। कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने भी जनता से अपील की थी कि, वह आप को पंजाब की सभी 13 सीटें जिताए। अब आप के अन्य नेता भी ऐसी ही बात कर रहे हैं। भले ही यह फाइनल नहीं है, लेकिन 'आप' के इस रुख को कांग्रेस पर दबाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।

अहम बात यह है कि, कांग्रेस भी यहां समझौते के मूड में नहीं है बल्कि वह भी सभी सीटों पर दावेदारी कर रही है। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर राजा वड़िंग ने कहा कि, पार्टी सभी 13 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। उन्होंने कहा कि हमारी तो यही दावेदारी है, लेकिन आखिरी फैसला तो हाईकमान को ही करना है। अमरिंदर ने कहा कि, मुझे उम्मीद है कि कोई फैसला लेने से पहले हमसे भी सलाह दी जाएगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल फिलहाल 10 दिनों के लिए पंजाब के होशियारपुर में विपश्यना के लिए निकले हैं।

### 6 राज्यों की 230 सीटें में कांग्रेस के हाथ आएंगी कितनीं...?

इंडिया अलायंस के लिए सीट शेयरिंग एक गंभीर मसला बना हुआ है। बंगाल में ममता बेनर्जी तीन से ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं बिहार में भी लगभग इतनी ही सीटें महागठबंधन में उसे मिलने की संभावना है। यूपी में अखिलेश यादव के भी तेवर सख्त हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि, बंगाल से पंजाब तक कांग्रेस के हाथ लड़ने के लिए कितनी लोकसभा सीटें आती हैं। दरअसल बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 230 सीटें आती हैं। ऐसे में इन राज्यों में यदि कांग्रेस का शेयर कम रहा तो फिर उसके लिए चुनाव बाद की स्थितियां कठिन होंगी।

# संसद में तीन नए बिल, मॉब लिंचिंग अपराध पर होगी फांसी की सजा

**नई दिल्ली, एजेंसी।**

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को तीन नए आपराधिक कानून विधेयक पर बोलते हुए लोकसभा में कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सीआरपीसी) में पहले 484 धाराएं थीं, अब 531 होंगी। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं। अमित शाह ने कहा कि, सीआरपीसी के 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी हैं और 14 धाराओं को हटा दिया गया है।

लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा कि, मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने (कांग्रेस) भी वर्षों देश में शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए।

उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट 1872) की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा।

### अंग्रेजों का काला राजद्रोह कानून निरस्त

लोकसभा में शाह ने कहा कि, राजद्रोह जैसे अंग्रेजों के काले कानून को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह देशद्रोह कानून लाया गया है। देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा। सशस्त्र विद्रोह करने पर जेल होगी। उन्होंने कहा कि, पुराने कानून तत्कालीन कानून विदेशी शासकों द्वारा अपना वर्चस्व बनाए रखने में मदद के लिए बनाए गए थे। नए कानून हमारे संविधान के मूल मूल्यों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के लिए समान व्यवहार को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

# हम जरूर गौर करेंगे... पीएम मोदी

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक इंटरव्यू में अमेरिका में एक भारतीय की हत्या की साजिश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, अगर कोई हमें किसी भी तरह की जानकारी देता है, तो हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया है, तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। यह पता चला है कि, गुरपतवंत सिंह पन्नून, जिसे 1 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा 'नामित व्यक्तिगत आतंकवादी' घोषित किया गया है, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देते हुए, पंजाब स्थित गैंगस्टरों और युवाओं को खालिस्तान के लिए लड़ने के लिए सक्रिय रूप से उकसा रहा है। इसका खुलासा एनआईए जांच में भी हुआ है। पन्नून 2019 से एनआईए की नजर में है जब आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने उसके खिलाफ अपना पहला मामला दर्ज किया था।

इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने भी चरमपंथी गतिविधियों पर चिंता जताई और कहा, भारत विदेशों में स्थित कुछ चरमपंथी समूहों की गतिविधियों को लेकर बेहद चिंतित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ये तत्व डराने-धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए मजबूत द्विदलीय समर्थन है, जो एक परिपक्व और स्थिर साझेदारी का स्पष्ट संकेतक है।सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग हमारी साझेदारी का एक प्रमुख घटक रहा है।

पीएम मोदी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कुछ घटनाओं को दोनों देशों के राजनयिक संबंधों से जोड़ना उचित है। मई में, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा के लिए अमेरिका का दौरा किया। जिसके बाद, बाइडन सितंबर में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुए जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए।

### उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल करने का मामला पकड़ रहा तूल

**एएनआई, नई दिल्ली।** सदन में टीएमसी सांसद कल्याण बेनर्जी द्वारा राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष लगातार धनखड़ की मिमिक्री को लेकर विपक्ष पर हावी हो रहा है। वहीं, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने के लिए टीएमसी सांसद कल्याण बेनर्जी के खिलाफ राज्यसभा और लोकसभा की नैतिक समितियों में शिकायत दर्ज कराई है। इस दौरान अपनी शिकायत में उन्होंने कल्याण बेनर्जी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और इसमें शामिल अन्य सभी सांसदों को निष्कासित करने की मांग की है।

# एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर अमृतपाल

**चंडीगढ़, एजेंसी।**

हत्या समेत कई संगीन वारदातों में वांछित गैंगस्टर अमृतपाल सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर ले जा रही थी। इस बीच उसने हथकड़ी में छिपाई पिस्तौल से फायर झोंककर भागने की कोशिश की लेकिन, एनकाउंटर में पुलिस टीम ने उसे ढेर कर दिया है। इस हमले में पुलिस के दो अधिकारी भी घायल हो गए।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 22 वर्षीय अमृतपाल सिंह को दो किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी के लिए जंडियाला गुरु ले जाया गया था। उन्होंने बताया कि, उसने हथकड़ी पहने हुए ही वहां छिपाई गई पिस्तौल से पुलिस टीम पर गोली चलाई और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने गोलीबारी की, जिसमें गैंगस्टर की मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना में दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए।

अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतिंदर सिंह ने कहा, पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसने 2 किलोग्राम हेरोइन छिपा रखी है। हम उसे नशीले पदार्थों को बरामद करने के लिए यहां लाए थे। उसने नशीले पदार्थों के साथ एक पिस्तौल छिपा रखी थी और उसने गोलीबारी की। पुलिस अधिकारियों पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गए। जवाब में, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की और गैंगस्टर को मार गिराया।

# 2 और सांसद निलंबित, आंकड़ा पहुंचा 143 तक

**नई दिल्ली।**

लोकसभा में तख्तियां दिखाने और सदन की अवमानना करने को लेकर बुधवार को दो और विपक्षी सदस्यों को संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। सदन की अवमानना के मामले में अब तक कुल 143 संसद सदस्यों को निलंबित किया जा चुका है। इससे पहले गत सप्ताह गुरुवार को 13 सदस्यों, सोमवार को 33 तथा मंगलवार को 49 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था।

आपराधिक कानूनों से संबंधित तीन विधेयकों पर चर्चा के बीच में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष के दो सदस्यों सी. थॉमस और एएम आरिफ का नाम लेकर उन्हें आसन की अवमानना को लेकर संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। आरिफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के और सी. थॉमस केरल कांग्रेस के सांसद हैं।

### निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन

वहीं, विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं और सांसदों ने लोकसभा एवं राज्यसभा से 140 से अधिक सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि, सरकार 'विपक्ष मुक्त संसद' तथा 'एक पार्टी के शासन वाली व्यवस्था' चाहती है। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा कई अन्य नेता शामिल हुए।

निलंबित लोकसभा सदस्यों में शामिल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी इस तरह से इतने सांसदों को सदन से बाहर नहीं किया गया। यह व्यवस्था का ऐतिहासिक दुरुपयोग है। सरकार चाहती है कि विपक्ष मुक्त लोकसभा और विपक्ष मुक्त राज्यसभा हो।

### हम चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे- बोले मनोज झा

राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने कहा, हम चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं। हम गृह मंत्री से दोनों सदनों में बयान चाहते हैं। सुरक्षा चूक को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला मानना चाहिए। हमने गृह मंत्री के बयान की मांग की तो इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया, आपने (सरकार) लोकतंत्र की जननी का कत्ल करने की सुपारी ले ली है और वही आप कर रहे हैं। आपको प्रतिरोध मुक्त सड़क और विपक्ष मुक्त संसद चाहिए। मुबारक हो मोदी जी। आप इस देश को एक पार्टी के शासन वाली व्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं। सदन में तख्तियां लहराने और नारे लगाने के आरोप में पिछले कुछ दिनों के भीतर 143 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है।

# विदेशी ब्रांडों को मात दे रही एमपी की महुआ शराब

# ताज और मैरिएट जैसे होटलों में लोगों को महुआ शराब का चखाया जा रहा है स्वाद

*भोपाल। गोवा की फेनी और केरल की टोडी जैसे ही मध्यप्रदेश में भी परंपरागत महुआ शराब बिकनी शुरू हो गई है। आप भी इसे बनाकर करोड़ों कमा सकते हैं। इस काम में मध्यप्रदेश आबकारी विभाग मदद करेगा. इस शराब के लिए एजेंसी हायर की जा रही है. जो कि पूरे प्रदेश में महुआ शराब को बनाने, मार्केटिंग करने व बिक्री के लिए आउटलेट्स खोलेगी। एजेंसी निर्यात भी करवाएगी।*

सरकार ने एक साल पहले आदिवासियों को सशक्त बनाने और आगे बढ़ाने के लिए राज्य की ऐतिहासिक महुआ शराब के लिए नई आबकारी नीति बनाई थी। इसे हैरिटेज लिकर नीति कहा गया है, इसमें वैट और लाइसेंस फीस में छूट का प्रावधान रखा गया है। अलीराजपुर में मोंड और डिडोंरी में मोहुलो ब्रांड से शराब बननी शुरू हो चुकी है। अब मध्यप्रदेश सरकार महिला स्व सहायता समूह के जरिए हैरिटेज शराब के निर्माण को प्रोत्साहित करने जा रही है। इसके तहत एक एजेंसी को रखने का टेंडर हो चुका है।

आबकारी आयुक्त ने बताया कि, जनवरी 2024 से यह काम शुरू हो जाएगा. इससे प्रदेश के आदिवासी इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और आय में बढोतरी होगी।

### अब एजेंसी बताएगी शराब के फायदे

विभाग के अफसरों ने बताया कि, मार्केटिंग एजेंसी हेरिटेज शराब के लिए जागरूकता बढ़ाने का काम करेगी। यानी लोगों के बीच शराब का उपभोग बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार करेगी। इसके लिए महुआ की शराब के फायदे बताकर नए ग्राहक बनाए जाएंगे। इसके अलावा, महिला स्व सहायता समूहों को शराब का उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चे माल की खरीद, मशीनरी, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंटरी और स्टोरेज मैनेजमेंट में मदद करते हुए विभिन्न योजनाओं के जरिए लोन दिलवाया जाएगा। एजेंसी दूसरे राज्यों में भी रिटेल आउटलेट काउंटर खुलवाएगी। यह आउटलेट से आर्डर लेकर सप्लाई चैन खड़ी करेगी. नीतिगत मामलों में आबकारी विभाग और मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के साथ सामंजस स्थापित करेगी। एजेंसी को भी मुनाफे में 10 प्रतिशत का हिस्सा मिलेगा।

### मौजूदा दुकानों से अलग खोले जाएंगे नई दुकाने

वर्तमान दुकानों से हटकर अलग से आउटलेट खोले जाएंगे। शराब की कीमत विभाग ही तय करेगा। इसमें मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम और उत्पादन शुल्क से भी मदद ली जाएगी। वहीं, एक अगस्त से हैरिटेज शराब प्रदेश में बिकनी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश ताज और मैरिएट जैसे होटलों में लोगों को महुआ का स्वाद चखाया जा रहा है।

### ब्रिटिश काल में बैन कर दी गई थी महुआ

महुआ के पेड़ से झरने वाले फूलों से यह शराब बनाई जाती है. सदियों तक यह ड्रिंक और महुआ के फूल आदिवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रही, जिसे ब्रिटिश काल में बैन कर दिया गया था. झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों की आदिवासी जातियों का महुआ के साथ कनेक्शन रहा है.।

## समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित

## विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओ का लाभ दिए जाने के लिए सतत भ्रमण करे- कलेक्टर

**माही की गूंज, झाबुआ।**

कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा द्वारा कलेक्टर सभाकक्ष में सुबह 11 बजे समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में कलेक्टर द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न विभागों की योजनाओ के तहत प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री एवं उन पर की जा रही कार्यवाही की जनपदवार समीक्षा की गई।

साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रदान की जा रही सेवाओ में सिकल सेल एवं टीबी की जाँच तथा आयुष्मान कार्ड प्राथमिकता से बनाए जाने हेतु एवं राजस्व विभाग अंतर्गत दी जा रही सेवाओं के अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने हेतु राजस्व विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत समस्त विभाग प्रमुखों को यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओ का लाभ दिए जाने के लिए सतत भ्रमण करने हेतु कहा गया।

समयावधि पत्रों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन 181 पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा कर एल 3 एवं एल 4 लेवल पर लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निराकृत करने को कहा गया। कलेक्टर द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारियों से अपने क्षेत्रान्तर्गत आधार सेंटर की जाँच एवं खुले बोरिंग को सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थित रूप से ढकवाए जाने संबंधित कार्यवाही संबंधी समीक्षा की गई। साथ ही नगरीय क्षेत्रो में स्थित रेन बसेरो में रात्रि में ठहरने वाले व्यक्तियों हेतु ठंड से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्थाए करने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया।

बैठक में अधिकारियों की स्कूल, छात्रावासो एवं आश्रम का निरीक्षण एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानों, आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्रों एवं हॉस्टल्स के निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया।

## महिला के नपा कर्मचारी पर आरोपः राशन कार्ड बनाने के लिए शारीरिक संबंध बनाने का बनाया दबाव

**अनूपपुर।** जिले के बिजुरी नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की शिकायत की गई है। बैवा महिला ने राशन कार्ड बनाने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने की शिकायत एसपी को की है।

कर्मचारी पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ईश्वर साहू ने महिला से राशन कार्ड बनवाने के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। महिला के पति की मौत हो चुकी है।

महिला ने एसपी को शिकायत में बताया कि, 15 दिसंबर को ईश्वरलाल साहू एक अन्य व्यक्ति के साथ उसके घर पर पहुंचा। जहां साथ में आए एक अन्य व्यक्ति को ईश्वर लाल ने पटवारी बतलाया। तथा कहा कि, राशन कार्ड यदि बनवाना है, तो पटवारी साहब को 5 हजार देने पड़ेंगे। इस पर महिला ने इतने रुपये नहीं होने की बात कही।

महिला द्वारा आरोपित किया गया कि, ईश्वर साहू ने उससे कहा यदि पैसे नहीं है तो हम दोनों के साथ तुम्हें शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। तभी तुम्हारा राशन कार्ड का काम होगा। इसके बाद महिला ने डांटते हुए उन्हें अपने घर से निकाल दिया। इसके साथ ही महिला ने शिकायत में बताया कि, ईश्वर साहू द्वारा अन्य व्यक्ति को फर्जी पटवारी बनाकर महिला के साथ राशन कार्ड बनाने के नाम पर शारीरिक संबंध बनाना चाहता था।

## जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की जिला स्तरीय तकनीकी समूह की हुई बैठक

**माही की गूंज, झाबुआ।**

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खरीफ 2024 एवं रबी वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न फसलो के लिए ऋण मान का निर्धारण तथा फसलवार नगद एवं वस्तु ऋण सीमा का निर्धारण किए जाने पर चर्चा की गई।

जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक में अल्पकालीन फसली ऋण की तिथि निर्धारण, अल्पकालीन फसल ऋण के लिए व्यक्तिगत सदस्य की अधिकतम सीमा का निर्धारण, उद्यानिकी अंतर्गत फल-फूल एवं सब्जी हेतु ऋण दरों का निर्धारण, नाबार्ड द्वारा निर्धारित मध्यकालीन ऋण का निर्धारण, नाबार्ड द्वारा पशुपालन एवं मत्स्य व्यवसाय कृषको की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के विस्तारीकरण संबंधित भारत शासन की योजना विमान का निर्धारण किया गया।

# स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

## शिक्षक बच्चो को गुड टच और बेड टच के बारे में बताए – श्री शर्मा

**माही की गूंज, झाबुआ।**

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमती विधि सक्सेना के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार प्रथम जिला न्यायाधीश झाबुआ राजेन्द्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल, अधिवक्ता विश्वास शाह की उपस्थिति में 20 दिसम्बर को एक निजी स्कूल झाबुआ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ अतिथिगणों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया।

शिविर में प्रथम जिला न्यायाधीश झाबुआ राजेन्द्र कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि, बच्चे हमारे समाज का भविष्य हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि, हम उनके अधिकारों को समझें और उन्हें इन अधिकारों की रक्षा करने में मदद करें। श्री शर्मा ने पॉस्को एक्ट अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि, पॉक्सो एक्ट एक कानून है जो बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए बनाया गया है। यह कानून बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप या आपके आसपास कोई बच्चा यौन शोषण का शिकार हो रहा है, तो तुरंत पुलिस या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। उन्होंने शिक्षिकों से अपील की कि, वे बच्चों को इन विषयों के बारे में शिक्षित करें। उन्हें गुड टच और बेड टच के बारे में बताएं। उन्हें बताएं कि, अगर कोई उन्हें छूने की कोशिश करता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। मैं सभी बच्चों से भी अपील करता हूं कि, अगर आपके साथ कोई गलत होता है तो आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें या आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी कानूनी सहायता ले सकते हैं। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल ने स्कूली बच्चों को आईटी एक्ट, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य जैसे आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।

संबोधन की कड़ी में अधिवक्ता विश्वास शाह ने लीगल एंड डिफेंस काउसिंल सिस्टम की जानकारी देते हुए कहा कि, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम एक प्रणाली है जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करती है। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो गरीब और कमजोर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है। यदि आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर का संचालन कु. नीता पुरोहित एवं आभार शिक्षिका श्रीमती प्रियंका कुमावत ने माना।

## शासकीय कार्यालयों में सुशासन की शपथ होगी कल

**माही की गूंज, झाबुआ।**

देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर के एक दिन पहले 24 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 24 दिसम्बर रविवार एवं 23 दिसम्बर शनिवार को शासकीय अवकाश होने के कारण समस्त शासकीय कार्यालयों में 22 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे सुशासन की शपथ ली जाएगी। जिसमें सभी अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे।

## क्रिसमस पर बच्चों को जबरन सेंटा क्लाज नहीं बना सकेंगे स्कूल, होगी कार्रवाई

**माही की गूंज, शाजापुर।**

क्रिसमस पर्व पर बच्चों को स्कूलों में सांता क्लाज बनाया जाता है। इसे लेकर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध दर्ज कराया जाता रहा है। ऐसे में इस बार शाजापुर में इसे लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने बाकायदा लिखित आदेश जारी कर निजी और शासकीय स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों को सांता क्लाज बनाने के पहले अभिभावकों से अनुमति लें।

जिला शिक्षा अधिकारी दुबे द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि, क्रिसमस के अवसर पर आपके विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सहभागिता करने वाले एवं क्रिसमस ट्री, सांता क्लाज, विविध वेशभूषा एवं अन्य कोई पात्र बनाये जाने के लिए आपके द्वारा चयनीत छात्र/छात्राओं को उनके अभिभावक से लिखित अनुमति प्राप्त कर ही बनाया जाए।

**शिकायत पर होगी कार्रवाई**

किसी भी स्थिति में बिना अभिभावक की लिखित अनुमति के किसी भी छात्र-छात्रा की उक्त आयोजन में सहभागिता न कराई जाए। जिससे कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हों। अगर आदेश का उल्लंघन किया गया और किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद संज्ञान में आया तो आपकी संस्था के विरूद्ध एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

## पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्य में तेजी लाए- कलेक्टर

**माही की गूंज, मंदसौर।** कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने पशुपतिनाथ लोक निर्माण के संबंध में पशुपतिनाथ सभागार में बैठक ली। बैठक के दौरान निर्माण कार्य कर रही एजेंसी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि, पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्य में तेजी लाए। जिससे कार्य जल्दी पूर्ण हो सके। पशुपतिनाथ लोक के सभी द्वार भव्य एवं आकर्षक बनाएं, जो पर्यटकों को आकर्षित कर सके। उन्होंने कहा कि, लोक परिसर में पार्किंग व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, यात्री विश्राम, भोजनालय, बाथरूम, बैठक व्यवस्था, बहुत अच्छे से की जाए। इसके लिए पहले से प्लान भी तैयार करें। निर्माण कार्य के लिए पत्थर राजस्थान से आएंगे। कुछ समय पश्चात पत्थर जुड़वाने का काम भी शुरू हो जाएगा। मेला समाप्त होने के पश्चात कार्य की प्रगति और बढ़ेगी। जिससे कार्य जल्दी होगा। लोक परिसर में लाइटिंग व्यवस्था बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अलग-अलग कलर की लाइट लगाया जाए, जो की आकर्षण का केंद्र बने। पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्य की डिजाइन वास्तु शास्त्र को दिखाया जाए। जिससे इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सके। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत कुमार सत्यम, अपर कलेक्टर विशाल सिंह चैहान, पशुपतिनाथ लोक निर्माण कार्य ठेकेदार मौजूद थे।

# चुनाव के साथ दक्षिण एशिया में उभरती चुनौतियां

अब जबकि वर्ष 2023 खत्म होने को है, दक्षिण एशिया के तीन बड़े देश -भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान- 2024 में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों की तैयारी में मसरूफ हैं। भारत में हाल ही में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिली चुनावी विजय के साथ इस सत्ताधारी दल की लोकप्रियता और मजबूती देखने को मिली है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने देश के दक्षिणी राज्य तेलंगाना में सत्ता में वापसी की है। बांग्लादेश में अगले साल के जनवरी माह में तो पाकिस्तान में फरवरी में आम चुनाव होंगे। आगे चलकर श्रीलंका में भी राष्ट्रीय चुनाव होना है।

इसी दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज्जू के प्रतीकात्मक अनुरोध को स्वीकार करते हुए वहां तैनात लगभग 75 भारतीय सैनिकों की वापसी स्वीकार कर ली है। हालांकि ठीक इसी समय मालदीव में भारतीय मदद से बनने वाली विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय समझौता हुआ है। विगत में, भारत ने मालदीव की संप्रभुता कायम रखने हेतु वहां सैन्य बल भेजा था, जब 1988 में सशस्त्र गिरोह ने इस टापू की सत्ता हथिया ली थी।

वर्तमान में पाकिस्तान गंभीर आर्थिक दिवालियापन से गुजर रहा है। चुनाव की तैयारियों के मध्य, तमाम व्यावहारिक प्रयोजनों से, पाकिस्तान में राज सेना का ही है। कहने को लोकतंत्र है, लेकिन पाकिस्तान के बेताज बादशाह नवनियुक्त सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर हैं। यह भी तथ्य है कि पाकिस्तान के अन्य महत्वाकांक्षी सेनाध्यक्षों की भांति जनरल मुनीर को भी अमेरिका का वरदहस्त प्राप्त है और उन्हें अमेरिका यात्रा का निमंत्रण मिला। पाकिस्तानी सेना के जनसूचना विभाग ने जनरल मुनीर की अमेरिकी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के अलावा बाइडेन प्रशासन की अन्य वरिष्ठतम शख्सियतों के साथ भेंट कार्यक्रम की तारीखें काफी जोर-शोर से प्रचारित की थीं। जनरल मुनीर को उनके पूर्ववर्ती सेनाध्यक्ष बाजवा ने विशेष रूप से चुनकर अपनी जगह बैठाया है। बता दें कि अमेरिका के कहने पर यूक्रेन तक सैन्य सामग्री पहुंचाने में बाजवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इसी बीच अफगानिस्तान मामलों पर अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट पाकिस्तान पहुंचे और आतंकवाद से लड़ाई में पाकिस्तान के साथ अमेरिकी का पूर्ण सहयोग होने की घोषणा की है। जाहिर है बाइडेन प्रशासन की याददाश्त कमजोर है, लगता है वह दिन भूल गए, जब पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया करवा रखी थी। इसके अलावा वह भी भूल गया लगता है जब एक ओर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की निकासी हो रही थी तो दूसरी ओर तत्कालीन आईएसआई के इशारों पर तालिबान काबुल में सत्ता संभाल रहे थे। इमरान खान से चिढ़ रखने वाले जनरल मुनीर ने अमेरिका की यात्रा की है। लेकिन इन सबका पाकिस्तान का अपने सदाबहार दोस्त चीन के साथ रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल जनरल मुनीर का मुख्य ध्यान इमरान खान और उनके चेलों को अनेकानेक मामलों में फंसाने पर है। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की ब्यानबाजी उन्हें आगामी आम चुनाव में हिस्सा लेने से महरूम करवा सकती है।

बड़ी संख्या में अधिकारियों, सैनिकों और पूर्व-सैनिकों में इमरान खान को चुनाव लड़ने से वर्जित करने वाले प्रयासों को लेकर रोष है। सबसे अहम, लगता है इमरान खान को न्यायपालिका की प्रभावशाली सहायता प्राप्त है। तय कार्यक्रम के अनुसार 8 फरवरी, 2024 को पाकिस्तान में आम चुनाव करवाए जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल पाएगी और चुनाव में भाग लेने की इज़ाजत मिलेगी।

उधर, पाकिस्तानी सशस्त्र बलों को अब पश्तूनों से सीधी चुनौतियां दरपेश हैं, जो कि ड्यूरंड सीमा रेखा के दोनों ओर तालिबान के समर्थक हैं। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान से संवाद के सूत्र कायम रखकर काफी समझदारी की है। उम्मीद है आगे भी भारत अफगान लोगों को बेतरह जरूरी गेहूं की आपूर्ति जारी रखेगा। भारत से अफगानिस्तान को भेजी सामग्री बरास्ता पाकिस्तान की बजाय अब ईरान के चाबहार बंदरगाह से होकर पहुंच सकेगी। ऐसे में जब खुद मोदी सरकार आगामी आम चुनाव के लिए कमर कस रही है, बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को दरपेश सख्त मुकाबले से भारत के लिए नई चुनौतियां बन सकती हैं। बांग्लादेश में आवामी लीग के प्रति वर्तमान और पिछ्ली अमेरिकी सरकारों का पूर्वाग्रह जारी रहने से, भारत की पूरबी सीमाओं पर मुश्किलें जटिल बनी हैं। शेख हसीना की आवामी लीग के प्रति अमेरिकी पूर्वाग्रह बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त से कायम है। अमेरिका का यह रवैया इस तथ्य के मद्देनज़र हैरानी जनक है कि बांग्लादेश का चीन के साथ संबंध नपी-तुली मित्रता वाला है, जो कि चीन-पाकिस्तान के बीच परमाणु और सैन्य संबंधों से काफी अलग है, और अमेरिका को जिसकी न तो परवाह है न ही दिखाई देता है।

आवामी लीग के प्रति अमेरिका की खुन्नस शेख मुजीब-उर-रहमान के वक्त से है, जो उनकी पुत्री शेख हसीना के साथ भी कायम है। भारत में भी, गहन संशय है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीब-उर-रहमान की हत्या के पीछे विदेशी हाथ है। भारत और बांग्लादेश, दोनों की म्यांमार से थलीय सीमाएं साझा हैं। सीमापारीय आतंकवाद से निबटने में जहां भारत के म्यांमार के साथ निकट संबंध हैं वहीं रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले के कारण बांग्लादेश और म्यांमार के बीच तल्खी है। सशस्त्र विद्रोहियों से निपटने में म्यांमार के साथ भारत का सीमापारीय सहयोग काफी मजबूत है। मणिपुर की हालिया घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में उक्त सहयोग का होना काफी अहम है।

जी पार्थसारथी

भारत की दक्षिण-पूरबी सीमाओं पर आने वाले महीनों में तनाव और संभावित हिंसा में उभार देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश में भी आगामी आम चुनाव में हिंसा होने को लेकर चिंता है, जहां पर शेख हसीना की पंथ-निरपेक्ष सरकार को कट्टरवादी इस्लामिक तत्वों से चुनौतियां दरपेश हैं। बांग्लादेश और शेख हसीना को निजी तौर पर, अमेरिका और कनाडा के खिलाफ नाराज़गी जायज है, जिन्होंने दो पूर्व बांग्लादेश फौजी अफसरों को पनाह दी हुई है जिन्हें शेख मुजीब-उर-रहमान हत्याकांड में सजा सुनाई जा चुकी है। इन दोनों की सज़ा पर बांग्लादेश में क्रियान्वयन लंबित है।

नव वर्ष में बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में आम चुनाव होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में, अत्यधिक प्रभाव रखने वाली सेना, लोकप्रिय नेता इमरान खान को चुनाव लड़ने से बेदखल करने पर तुली हुई है। जबकि ठीक इसी वक्त मुल्क लगभग दिवालिया है और गुजारे के लिए अमेरिकी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की खैरात पर निर्भर है। बांग्लादेश में, अमेरिका और पाकिस्तान, दोनों नहीं चाहते कि शेख हसीना सत्ता में लौटें।

## जनपद पंचायत की कारगुजारियों का फिर हुआ बड़ा खुलासा

# प्रधानमंत्री आवास की राशि बिना कार्य के ही आहरण करने वाला मंत्री बहाल, मृतक रोजगार सहायक पर फटा बिल

## फर्जी रूप से निकाला भुगतान किया जमा, 18 हजार मजदूरी कहा गई साहब

**माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत**

जनपद पंचायत पेटलावद में फैले भ्रष्टाचार को अगर उजागर किया जाता है तो यहां भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की जगह उसको दबाने ओर निपटाने के लिए उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार किया जाता है। जनपद पंचायत पेटलावद की कारगुजारी एक बार फिर उजागर हुई है जहां बिना कार्य किये राशि आहरण करने के एक मामले में जबाबदारो ने राशि वसूल कर मामले को पुरानी परंपरा अनुसार खत्म कर दिया। मामला ग्राम पंचायत करडावद का है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि मे गबन का मामला सामने आया था। शिकायतकर्ता गोपाल आंजना द्वारा शिकायत के बाद पूरा मामला उजागर हुवा था और माही की गूंज द्वारा प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ खबरों के माध्यम से पूरा मामला उजागर किया गया था। शिकायतकर्ता को हर प्रकार के दिये प्रभोलन के बाद जब शिकायतकर्ता नही माना तो अधिकारीयो ने अपनी सेटिंग बिठा कर मामले को हवा कर दिया। पूरे मामले का खुलासा एक बार फिर सूचना अधिकार द्वारा निकाली गई जानकारी से हुवा है।

### ये था मामला

विकास खण्ड की ग्राम पंचायत करडावद में राजाराम आंजना के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुवा था लेकिन राजाराम ने ग्राम पंचायत से सेटिंग बिठा कर बिना निर्माण कार्य किये योजना की मिलने वाली राशि एक लाख बीस हजार ओर मजदूरी की राशि 18 हजार फर्जी जगह का जियो टैग कर हितग्राहि के खाते में डाल कर राशि की बंदरबाट कर ली। मामले की शिकायत के बाद अधिकारी इस मामले की जांच तक करने को तैयार नही थे और मामले को जैसे-तैसे रफा-दफा करने में जुट गए। गूँज द्वारा मामला उठाने के बाद बमुश्किल हुई जांच में आखिर भ्रष्टाचार उजागर हुवा ओर प्रधानमंत्री आवास की राशि मे बंदरबाट सामने आई।

### मामला दर्ज करने की मांग, थमाये थे कानूनी नोटिस

शासकीय राशि मे हेराफेरी उजागर ओर प्रमाणित होने के बाद शिकायतकर्ता ने शासकीय राशि के दुरुपयोग ओर अमानत में खयानत सहित पंचायत एक्ट के तहत 420 व अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की थी और इस सम्बंध में जिला कलेक्टर, जिला सीओ ओर जनपद सीईओ को कानूनी नोटिस भेज कर मामले में पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग करते हुवे नियमानुसार कार्यवाही नही होने पर जिम्मेदार अधिकारीयो के विरुद्ध न्यायालीन कार्यवाही करने की बात कही थी।

### बीच की गली निकाल कर दबा दिय्या मामला, मरे हुवे रोजगार सहायक पर फाड़ा बिल

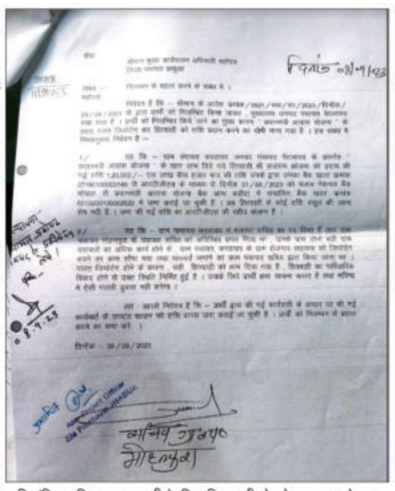

निलंबित सचिव द्वारा बहाली के लिए जिला सीओ को प्रस्तुत आवेदन।

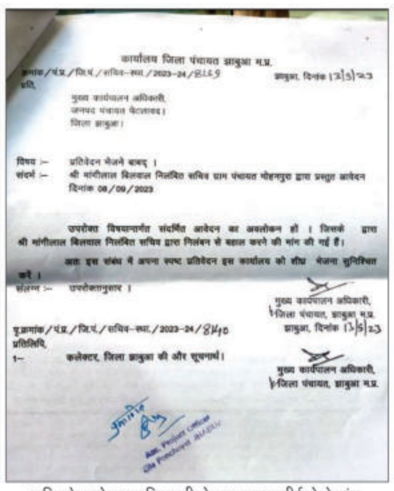

सचिव के आवेदन पर जिला सीओ द्वारा जनपद सीईओ से मांगा प्रतिवेदन।

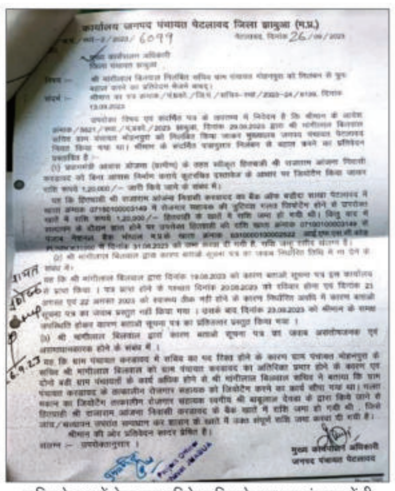

सचिव के पक्ष में भेजा गया प्रतिवेदन जिसके बाद मूल पंचायत में ही बहाल हुवा सचिव।

हितग्राही के माध्यम से योजना की राशि एक लाख बीस हजार जमा करने की रसीद।

इस प्रकार के सैकड़ों मामले पेटलावद जनपद में सामने आए हैं जिन्हें हमने उजागर किया है ज्यादातर मामलों में शिकायतकर्ता से मिलीभगत कर मामले निपटा दिए जाते हैं और फर्जी भुगतान के मामले वसुली के नाम पर फाइलों में दब कर रह जाते है। जिम्मेदार सचिव उपयंत्री और सरपंच लेनदेन कर कारण बताओ नोटिस तक सीमित कर दिए जाते हैं। लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता के मजबूत होने के कारण अधिकारीयो ने पुलिस प्रकरण से भ्रष्ट कों बचाने के लिए बीच का रास्ता निकालते हुवे हितग्राही से एक मुश्त राशि शासन के खाते में डलवा कर भ्रष्टाचार का बिल इस पंचायत के रोजगार सहायक पर फाड़ दिया गया जो पहले से मर्त हो चुका है। ग्राम पंचायत के सचिव ने अपने कथन में बताया कि उसकी गैरमौजूदगी में उसके आईडी पासवर्ड का दुरुपयोग रोजगार सहायक ने कर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। अब मर चुका रोजगार सहायक कैसे बताये की इस भ्रष्टाचार में उसकी क्या भूमिका थी।

### एक बीस जमा तो मजदूरी के 18 हजार कहां गए

भ्रष्टाचार के इस मामले में फस चुके सरपंच, सचिव, हितग्राही सहित अधिकारीयो ने बचने के लिए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी रकम कुल एक लाख बीस हजार रुपये एक मुश्त शासन के खाते में जमा कर दिए। जिसका खुलासा आरटीआई में निकले दस्तावेजो से हुवा। अधिकारीयो ने हितग्राही राजाराम आंजना के खाते से एक लाख बीस हजार जमा किये जिससे ये साफ हो गया की किस तरह केंद्र की राशि की बंदरबांट की जा रही है पकड़े गए तो चोर नही तो सरकारी माल अपना ओर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का साथ मिल जाये तो चोरी की राशि जमा करो और पाक साफ होंकर नोकरी पर बहाल हो जाओ। हालांकि योजना की कुल राशि का भुगतान एक लाख अठतिस हजार किय्या गया था। 18हजार का भुगतान फर्जी रूप से मजदूरों के खातों में किया गया क्योंकि जांच में साफ हो चुका था कि कोई काम किया ही नही गया तो मजदूरों का भुगतान कैसे हुवा। अधिकारीयो की कारिस्तानी साफ नजर आती है कि एक बड़ी रकम जमा करवा कर मामले को जैसे तैसे निपटाया गया हैं और बताया जा रहा है कि इसके लिए भी लेन देन किया गया।

### बहाल हुवा सचिव

जांच के दौरान भ्रष्टाचार पाये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया था। राशि जमा कर मंत्री साहब को वापस बहाल कर दिया गया। जिसे बड़े नियमो से किया गया।बकायदा सचिव ने बहाल होने के लिए जिला सीओ के समक्ष आवेदन पेश किया। जिस पर जिला सीओ ने जनपद सीईओ का प्रतिवेदन बुलाया। प्रतिवेदन में राशि जमा होने और म्रतक रोजगार सहायक द्वारा जियो टैग करना बता कर सचिव को मुक्त कर पुनः बहाल कर दिया गया। सबसे बड़ी बात जिला सीओ ओर जनपद सीईओ ने फर्जी मजदूरी भुगतान का कोई उल्लेख तक नही किया। जबकि शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत में ऐसे और भी मामले होने की शिकायत की थी जिंसमे आधे अधूरे निर्माण को पूरा भुगतान और हितग्राही के पास पहले से मकान बना होने के मामले भी थे जिसकी जांच की जानी थी लेकिन अधिकारीयो ने अपनी जांच को केवल एक मामले तक सीमित कर मामला खत्म कर दिया।

### अब आगे क्या ?

इस सम्बध में गूँज द्वारा शिकायतकर्ता गोपाल आंजना से चर्चा की तो उन्होंने ने बताया कि पूरे प्रकरण की प्रमाणित नकल प्राप्त कर ली हैं और वकील से कानूनी सलाह के बाद आगे की कार्यवाही जारी रखूंगा। पूरे मामले को देखने के बाद यही पता चलता है कि जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल किस कदर चल रहा है जहां मामलू चोरीयो के आरोप में कई लोग जेल में पहुँच जाते हैं या कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं वही शासन द्वारा दी जा रही राशि को जनपद के अधिकारी ऐसे ही लुटा रहे है और पकड़े जाने पर कानून की किताब को अपने हिसाब से पड़ कर चोरों ओर शासकीय राशि उड़ाने वालो को एक ओर भ्रष्टाचार कर बचा लेते हैं। जनपद पंचायत पेटलावद की कई पंचायतों के फर्जी भुगतान के मामले वसुली के नाम पर अधिकारियों की धूल खा रहे हैं ये जिम्मदारो के खुले भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था को गुमराह करने का पुख्ता प्रमाण है।

## यात्रा के प्रचार-प्रसार में लापरवाहीः सचिव और रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस

**माही की गूंज, पेटलावद।**

रविवार को रायपुरिया से शुरू हुई केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार-प्रसार में लापरवाही बरतने के लिए ग्राम पंचायत गोपालपुरा के सचिव और रोजगार सहायक को जनपद सीईओ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ग्राम पंचायत गोपालपुरा के सचिव नुरजी गामड़ ओर रोजगार सहायक मानसिंह सोलंकी को जनपद पंचायत सीईओ राजेश दीक्षित ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में बताया गया कि, विकसित भारत संकल्प यात्रा के सुचारू सफल संचालन के लिए निर्देशित किया गया था जिंसमे लापरवाही बरते हुए कार्य नही किया गया। सचिव और रोजगार सहायक से तीन दिन में जबाव देने के लिए तलब करने को कहा गया हैं।

## संस्कृत भारती के कार्यालय का हुआ शुभारंभ

**माही की गूंज, पेटलावद।**

संस्कृत भारती का पेटलावद नगर में कार्यालय का शुभारंभ थांदला रोड़ पर संस्कृत भारती के जिलाअध्यक्ष महेंद्रसिंह राठौर, संस्कृत प्रचारक मोहन डामर,शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य शिवराम खंडहर, वरिष्ठ समाजसेवी पारस गादिया, संस्कृत, हीरालाल पाटीदार अमरगढ़, मदन काग की उपस्थिति में किया गया। अतिथियों ने माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यालय का शुभारंभ किया। संस्कृत प्रचारक मोहन डामर ने कार्यालय शुभारंभ की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। श्री डामर ने बताया कि प्रत्येक सोमवार को इस कार्यालय पर बाहर से आने वाले से स्नेहीजनों मुलाकात कर संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने की रूपरेखा बनाई जायेगी। इस मौके पर गोपाल मावी, करण भूरिया चैनपुरा, आदि मौजूद रहे।

## शा. उमावि में बालिकाओं का शालेय स्वास्थ्य प्रशिक्षण संपन्न

**माही की गूंज, थांदला।**

शा. कन्या उमावि थांदला में बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल अस्पताल थांदला के नेत्र चिकि. सहायक राजू नायक व डॉ. शैलेष बारिया हेल्थ ऑफिसर सुश्री प्रीति सोलंकी एवं श्रीमती मीरा ओरा द्वारा आशा सहयोगिनी श्रीमती साधना डामोर, आशा कार्यकर्ता श्रीमती ममता अमलियार, अनीता, रमिला कटारा ,ललिता डामोर के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिसके अंतर्गत श्रीमती विनीता मंसारे, एएनएम श्रीमती अनिता धानक द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य शिक्षा के साथ बालिकाओं की सर्वांगीण मानसिक, शारीरिक विकास हेतु स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत उपचार परामर्श दिया गया। लगातार दो दिन तक कुल 999 छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी एसएनएस श्रीवास्तव द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रभारी सेक्टर पर्यवेक्षक प्रवीण धमांनिया द्वारा शासन के विकसित भारत संकल्प के मूल ध्येय में एनीमिया मुक्त भारत की महता तथा साप्ताहिक आयरन अनुपूरण कार्यक्रम विषय पर प्रेरक उद्बोधन संस्था में बालिकाओं को दिया गया।

## दुपहिया वाहनो की टक्कर में एक मासूम सहित दो की मौत

**माही की गूंज, रतलाम।**

जिले के रावटी थाना क्षेत्र में ग्राम रावटी के समीप ग्राम मोलावा में दो बाइकों में हुई जोरदार भिड़ंत में एक मासूम सहित दो की मौत हो गई है। मृतकों में बापू पिता बालू (26) व आशीष उर्फ आयुष (3) शामिल हैं। मृतक आयुष के पिता की हालत गंभीर होने पर उन्हें रतलाम रेफर किया है। ग्राम मोलावा में एक ओर से बाइक पर आशीष और बन्टी दोनों पिता-पुत्र जा रहे थे। इस दौरान सामने से दूसरी बाईक जिसपर बापू पिता बालू और बहादुर पिता हरिंगा आ रहे थें। दोनों की बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि, आशीष पिता बन्टी और दूसरी बाइक पर बैठे बापू पिता बालू की मौत हो गई। जबकि बन्टी और बहादुर घायल हो गए, जिन्हे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

## अटका मंत्रिमंडलः निर्मला भूरिया को मंत्रिमंडल में जगह मिलने का हो रहा इंतजार

**माही की गूंज, पेटलावद।**

मध्यप्रदेश में सरकार बने लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नही हो पाया है। मुख्यमंत्री के लिए चली माथापच्ची के बाद डॉक्टर मौहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और विगत आठ दिनों से मौहन यादव की नई टीम मंत्रिमंडल का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहै है। मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद से रोज मंत्री मण्डल पर चर्चा हो रही है और रोज मीडिया की खबरों ओर सोशल मीडिया पर सम्भावित मंत्रियों की सूची ओर संख्या वाइरल हो रही है। क्षेत्र से मंत्री पद को लेकर निर्मला भूरिया का नाम सूची में अग्रणीय है और क्षेत्र को उम्मीद् है इस बार झाबुआ जिले के हिस्से में मंत्री पद आएगा।

### अभी और करना पड़ सकता है इंतजार

जिस तरह से खबरे आ रही है अभी मंत्री मण्डल के लिए ओर इंतजार करना पड़ सकता है। मंत्रियों के नामो को लेकर दिल्ली में चर्चा का दौर जारी है। इस बार मुख्यमंत्री के साथ-साथ मंत्रियों के नाम भी दिल्ली दरबार से ही तय होना है। पेटलावद विधायक निर्मला भूरिया पांचवी बार विधानसभा पहुंची है, अजजा महिला विधायक को मंत्री मण्डल में जगह मिलने की सभावना व्यक्त की जा रही है।

### 15 या 30 मंत्री पर निर्भर भूरिया का मंत्री बनना

प्रदेश की सरकार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में भाजपा पहली खेप में कितने मंत्री बनाती हैं ये महत्त्वपूर्ण है। चर्चाओ के है कि, पहले दौर में लगभग 15 से 20 मंत्रीयो के नाम तय हो सकते हैं। यदि मंत्रिमंडल में इतनी ही संख्या रहती हैं तो निर्मला भूरिया के नाम पहली सूची में मुश्किल में पड़ सकता है। वही 30 मंत्रियों के नामो की घोषणा होती है तो निर्मला भूरिया के नाम पर मुहर लग सकती है माना जा रहा है।

## वर्षों बाद स्कूल में हुआ हैंडपंप खनन

**माही की गूंज, काकनवानी। नरेश पांचाल**

काकनवानी मुख्य बाजार के बीचो-बीच कन्या माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहा है। जहां वर्षों पूर्व एक हैंडपंप खनन किया गया था जो कुछ समय में बंद हो गया। उसके पश्चात इस स्कूल में पानी के लिए काफी दिक्कत आती रही। यहां के शिक्षक अपने जेब से पैसा देकर रोजाना पानी भरवा रहे थे, करीब 10 वर्षों से यहां हैंडपंप खनन की मांग की जा रही थी। बिना पानी के शिक्षक एवं बच्चे सभी परेशान हो रहे थे। कई वर्षों से शिक्षक एवं प्राचार्य अपनी जेब से पैसा खर्च कर बच्चों को पानी उपलब्ध करवाया करते थे। एक बड़े लंबे समय के उपरांत आज ग्राम पंचायत की और से कन्या प्राथमिक विद्यालय में हैंडपंप खनन किया गया हैं। हैडपंप खनन के वक्त सरपंच सांता देवी निनामा एवं सरपंच पति बाबू निनामा द्वारा पूजन कर मशीन लगाई गई। इस मौके पर बाबू पांचाल, राहुल पांचाल, जवान सिंह बारिया, राकेश धमनिया, सीतु भूरिया, प्राचार्य बीनू कटारा, बहादुर बारिया आदि उपस्थित थे।

## संपादकीय

# राजनीतिक गहमागहमी के बीच ''टेली कम्युनिकेशन बिल''

संसद की सुरक्षा में सेंध और उसके बाद उपजी राजनीतिक गहमागहमी के दौरान सांसदों के निलंबन के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ने लोकसभा में ''टेली कम्युनिकेशन बिल 2023'' के नए स्वरूप को पेश किया। इसमें जहां कई दृष्टियों से उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी गई है, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रसंगवश सरकार को जो नए अधिकार दिए गए हैं, उनको लेकर निजता व व्यक्तिगत आजादी की चिंताओं को भी अभिव्यक्त किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि, बिल सरकार को नागरिकों की निजता में हस्तक्षेप के असीमित अधिकार देता है। वहीं दूसरी ओर नया टेलीकॉम बिल कई तरह से मोबाइल यूजर्स को राहत भी देता है। यदि कोई बिना वजह टेलीफोन उपभोक्ता को परेशान करता है, तो उस पर 50 हजार से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ता को सिम जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बॉयोमेट्रिक पहचान का प्रावधान रखा गया है। यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, उसे व प्रबंधन को निलंबित करने का अधिकार देगा। दरअसल, यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा, जो अब तक टेलीकॉम सेक्टर को संचालित करता रहा है। साथ ही सरकार को बाजार में प्रतिस्पर्धा, टेलीकॉम नेटवर्क की उपलब्धता व निरंतरता सुनिश्चित करने का अधिकार भी देगा। इससे टेलीक़ॉम के क्षेत्र में कार्यरत देशी-विदेशी कंपनियों को लाभ मिलेगा। साथ ही लगातार अनचाही कॉल से अब राहत की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले ट्राई की तरफ से भी प्रमोशनल व बैंक कॉल्स की बढ़ोतरी रोकने के लिए कई सुझाव भी दिए गए थे। अब प्रोफेशनल मैसेज भेजने के लिए ग्राहक की अनुमति लेनी होगी। वहीं नए संशोधन में टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए पेनल्टी की रकम को 50 करोड़ से 5 करोड़ किया गया है। इसके अलावा ओटीटी के लिए नियमों को भी तय किया गया है। टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स की शिकायत दर्ज कराने को ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाएंगी। लेकिन दूसरी ओर नए दूरसंचार विधेयक को लेकर विपक्षी दल चिंता भी जता रहे हैं कि, इस बिल के जरिए सरकार को नागरिकों के संदेशों में हस्तक्षेप करने की अधिक शक्तियां मिल जाएंगी। बिल में प्रावधान है कि, व्हाट्सएप जैसी सेवाओं और ई-मेल प्रदाताओं को दूरसंचार सेवाओं के दायरे में लाया जाएगा। विधेयक में किसी भी तरह अवैध रूप से फोन टैपिंग और अनधिकृत डेटा ट्रांसफर पर तीन वर्ष तक कैद या 2 करोड़ तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। राष्ट्रीय सुरक्षा हित के लिए अस्थाई रूप से सरकार दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रण में ले सकेगी। दरअसल, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश नया विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार(गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1950 को निरस्त करेगा। इस बिल को पेश करते वक्त बसपा के एक सांसद ने इसे धन विधेयक के रूप में पेश करने का विरोध किया, जो इसे राज्यसभा की चर्चा से बाहर रखता है। उन्होंने इस बिल से जुड़ी गोपनीयता संबंधी चिंताओं के चलते संसदीय समिति को भेजने की भी मांग की थी। विधेयक कुछ उपग्रह आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रशासनिक आवंटन के जरिए स्पेक्ट्रम प्रदान करने का अधिकार भी देता है। जिसके चलते कई नामी अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनियों व कुछ भारतीय कंपनियों की उपग्रह संचार परियोजनाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। विधेयक में प्रावधान है कि, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और संवाददाताओं के संदेशों को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, बशर्ते वे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा न हों। नि:संदेह, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि अवांछित कॉल से लोग बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन साथ ही यह जरूरी है कि, नागरिकों की निजता व लोकतांत्रिक अधिकारों का भी अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। समय के साथ कानूनों को व्यावहारिक बनाया जाना बेहद जरूरी है। लेकिन ये कानून सत्ता को निरंकुश व्यवहार का अवसर न दें। सरकार की रीतियां-नीतियां लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ही होनी चाहिए।

# बिना चर्चा बिल पारित करने...? 3 दिन में 92 सांसद निलंबित

सनत कुमार जैन

संसद के शीतकालीन सत्र में बहुत महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होनी थी। बिलों पर यदि चर्चा होती, तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़तीं। संसद में जिस बिल पर 15 घंटे चर्चा करानी थी, वह बिल मात्र 5 से 6 मिनट में पारित हो गया। संसद में जो हंगामा चल रहा है। वह सत्ता पक्ष का प्रायोजित तरीका है। सत्ता पक्ष द्वारा जानबूझकर विपक्ष को उत्तेजित कर दिया जाता है, उत्तेजित विपक्ष को चर्चा में भाग लेने की बजाय हो हल्ला और हंगामा करने के लिए बाध्य कर दिया जाए। हंगामे के बीच बिल पारित करा लिए जाएं। ऐसे बहुत से बिल, मनी बिल के रूप में पेश किए जा रहे हैं। जो मनी बिल के रूप में पेश नहीं हो सकते हैं, आसंदी भी इसमें गफलत बरत रही है। जो सत्ता पक्ष को ऐसा करने दे रही है। हल्ला और हो-हंगामा के बीच में बहुमत के आधार पर बिल पास करने का सत्ता पक्ष ने यह एक अलग तरीका निकाला है। संसद में हमला हुआ था। इस हमले में युवाओं ने प्रदर्शन कर महंगाई और बेरोजगारी से संबंधित मांग उठाई थी। इस हमले में किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आतंक का वातावरण जरूर बना। उस हमले को लेकर विपक्ष की मांग है, कि गृहमंत्री सदन में आकर अपना वक्तव्य दें। उस पर चर्चा की जाए। सत्ता पक्ष द्वारा

विपक्ष की यह मांग नहीं मानी गई, जिसके कारण सदन के दोनों सदनों में पिछले चार दिनों से हंगामा हो रहा है। दोनों सदनों से महज तीन दिन में 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। जो स्वतंत्रता के बाद से अभी तक का सांसदों को निलंबित किए जाने का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री संसद के बाहर मीडिया और कार्यक्रम के दौरान संसद पर हुए हमले के बारे में जानकारी देते हैं। सदन के अंदर चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में यह गतिरोध जानबूझकर बनाया गया है। यह स्वाभाविक प्रतिरोध नहीं है। सत्ता पक्ष चाहता है, कि सदन की कार्रवाई के दौरान हो-हल्ला और हंगामा होता रहे। विपक्ष के हो-हल्ला के बीच सरकार अपने बिल संसद द्वारा बिना चर्चा के पास कर लिए जाएं। जब सारे बिल पास हो जाएंगे, तब सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। पिछले कई सत्रों में भी यही देखने को मिला है। वैसे भी मौजूदा सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी सत्र है। इसके बाद आम चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष को जाना होगा। बहरहाल जो घटनाएं संसद के अंदर हो रही हैं, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारतीय संविधान एवं संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं हैं। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हुए बेल पर आ जाना और तख्ती लेकर प्रदर्शन करने के विरोध में 92 सांसदों का निलंबन मात्र तीन दिनों में कर देना। इसे बहुमत का दुरुपयोग ही माना जा सकता है। ठीक है, अभी आप सत्ता में हैं, बहुमत में हैं, बहुमत के आधार पर सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इससे आसन्दी की गरिमा भी कम हो रही है। आसंदी पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। जैसा स्कूल और कॉलेज में भी छात्रों के साथ शिक्षक और प्रिंसिपल नहीं कर पाते हैं, वैसा व्यवहार राज्यसभा और लोकसभा की आसन्दी द्वारा सांसदों को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। इससे सांसदों और संसद की गरिमा भी गिर रही है। यह सारा देश देख रहा है। सदन में बहुमत के आधार पर सत्ता पक्ष ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वहीं विपक्ष की मांग को अनसुना करते हुए विपक्ष को एक तरह से, उनके अल्पमत होने का एहसास करने का काम भी सत्ता पक्ष और आसंदी द्वारा किया जा रहा है। यह अभी सही ठहराया जा सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह से संसदीय परंपराओं और गरिमा का अपमान हो रहा है। संसदीय गरिमा तार-तार हो रही है। संसद की आसंदी को विवादास्पद बनाया जा रहा है। इसका असर आने वाले समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर ही पड़ने वाला है। जो नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं। उनमें बार-बार संशोधन करना पड़ रहा है। जनता की आवाज जब संसद के अंदर नहीं सुनी जाएगी। बिना बहस के कानून बनाए जाएंगे। बिल पास करते समय सभी पक्षों को नहीं सुना जाएगा। मीडिया द्वारा जनता की आवाज नहीं उठाई जाएगी। उसका दुष्परिणाम है, जो संसद में आतंक की घटना हुई है। महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं ने विरोध करने का जो तरीका अपनाया है। वह कभी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ अपनाया था। उस समय भी जनता को अपना पक्ष रखने की आजादी नहीं थी। कुछ इसी तरह की स्थितियां अभी देखने को मिलने लगी हैं। इसके दुष्परिणाम जल्द ही देश के सामने आ सकते हैं। जब संसद चुप हो जाती है। तब जनता बगावती हो जाती है। और जब बगावती जनता सड़कों पर आ जाती है, तो उसको नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होता है। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भारत में कभी भी बगावत ओर क्रांति का इतिहास नहीं है, लेकिन अब यह स्थिति बनने लगी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की है। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया सत्ता के साथ कदमताल कर रहा है। जनता उपेक्षित है। यह स्थिति हमेशा से बगावत और क्रांति का कारण बनती है, यह वर्तमान सत्ता को समझना होगा।

# क्या विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल हैं...?

हाल में संपन्न राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम के विधानसभा चुनावों में कई कारणों से पूरे देश की भारी दिलचस्पी थी। भाजपा पिछले दस सालों से केंद्र में सत्ता में है और उसने जो नीतियाँ लागू की हैं, उनका देश पर भयावह प्रभाव पड़ा है। चाहे वह नोटबंदी हो, जीएसटी हो या रातोंरात लागू किया गया कोरोना लॉकडाउन दृ सबसे आम जनता की खासी फजीहत हुई। देश में सरकारें और ज्यादा तानाशाह होती जा रही हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर तरह-तरह की रोकें लगाई जा रही हैं। हंगर इंडेक्स में देश की गिरती हुई स्थिति और लोगों की बढ़ती परेशानियाँ बहुत कुछ बता रही हैं। भाजपा सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटा दिया है। हमें बताया गया था कि इससे अतिवाद कम होगा। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देश भर में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं और अलग-अलग स्थानों पर ईसाईयों के खिलाफ भी हिंसा हो रही है। इस पृष्ठभूमि में विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन का गठन किया। ऐसा कहा जा रहा था कि यह गठबंधन हमारे संविधान में निहित 'आईडिया ऑफ़ इंडिया' को संरक्षित रखने का प्रयास करेगा। सन 2024 के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में इस गठबंधन से बहुत उम्मीदें थीं।

मगर ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनावों के नतीजों ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस के राज्य-स्तरीय नेतृत्वों ने मनमानी करते हुए गठबंधन के अन्य दलों की उपेक्षा की। इससे दूसरी पार्टियाँ काफी नाराज़ हो गईं और गठबंधन के और मज़बूत होने की राह बाधित हो गयी। कांग्रेस केवल तेलंगाना में जीत हासिल कर सकी और हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ा। ये नतीजे चौंकाने वाले हैं क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल्स ने भविष्यवाणी की थी कि इन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं बेहतर रहेगा। इसलिए, कांग्रेस की हार एक पहेली बन गयी है।

यह सही है कि यदि कांग्रेस का अन्य राष्ट्रीय एवं छोटे दलों के साथ गठबंधन होता तो उसका प्रदर्शन बेहतर होता। फिर भी, इन राज्यों में उसकी हार का तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाते समय इस पहलू पर इंडिया गठबंधन के सदस्यों को ध्यान देना होगा।

इन परिणामों का एक पक्ष यह भी है कि अधिकांश दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो गया है। कुछ टिप्पणीकारों का तर्क है कि भाजपा की हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीति के प्रति समर्थन मुख्यतः हिन्दी-भाषी राज्यों या काऊ बेल्ट तक सीमित है। कांग्रेस और अन्य दलों को इस बात तथ्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि उसके तमाम दावों के बावजूद भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। यदि हम इन पांच राज्यों में डाले गए कुल वोटों की बात करें तो कांग्रेस को 4.92 करोड़ वोट मिले हैं जबकि भाजपा को 4.81 करोड वोट ही हासिल हुए हैं। इसके अलावा मिजोरम, जहां अभी तक एनडीए गठबंधन की सरकार थी, भी उसके हाथ से निकल गया है।

कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने के बारे में भी कयास लगाए जा रहे हैं। यह कार्यकर्ताओं की त्वरित प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन समय बीतने के साथ पार्टी कार्यकता, तेलंगाना की जीत और प्रतिद्वंद्वी भाजपा की तुलना में अच्छे खासे अधिक वोट हासिल करने को लेकर दुबारा जोश में आ सकते हैं। समय के साथ निराशा का भाव समाप्त हो जाएगा क्योंकि नेतृत्व स्थिति का सामना करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। 'भारत जोड़ो यात्रा' इस दिशा में एक बड़ा कदम थी। पर्दे के पीछे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों और जोश पुनर्जीवित होने से पार्टी के उत्साह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा की जा सकती है।

महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या वे सभी दल, जो इंडिया गठबंधन में शामिल थे, एक बार फिर गठबंधन के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे? चुनाव के नतीजों से इंडिया गठबंधन को धक्का लगा है। इन तीन बड़े राज्यों में कांग्रेस की हार से कांग्रेस नेतृत्व चिंतन करेगा और उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करेगा जिनके चलते गठबंधन के अन्य सदस्य नाराज हैं। विपक्षी दल यह अच्छी तरह जानते हैं कि वे अलग-अलग रहकर भाजपा की विशालकाय चुनावी मशीनरी का मुकाबला नहीं कर सकते। भाजपा के पास मानव संसाधन और धन प्रचुर मात्रा में हैं और उसमें दादागिरी करने की भी बहुत क्षमता है। मीडिया भी केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी के चरणों में नतमस्तक है।

विपक्षी दलों को यह एहसास भी है कि भाजपा अकेली नहीं है। उसे आरएसएस के प्रचारकों और स्वयंसेवकों की पूरी सहायता उपलब्ध है। वे यह भी जानते हैं कि आरएसएस के सहयोगी संगठन वीएचपी, एबीव्हीपी, बजरंग दल, वनवासी कल्याण आश्रम और उससे जुड़ी अन्य संस्थाएं हर चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। चुनावी बांडों से प्राप्त अकूत धन, हिन्दू राष्ट्रवादी विचारधारा को एनआरआई का समर्थन और बड़े उद्योग समूह, जिन्हें भाजपा बहुत तरह की छूटें दे रही हैं, सब भाजपा के मददगार हैं। इस तथ्य से भी वे अवगत हैं।

विपक्षी दलों को यह अहसास भी है कि भाजपा देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना चाहती है। वह खुलकर और दबे-छुपे ढंग से भारतीय संविधान के मूल्यों को कमजोर कर रही है। ईडी, आयकर विभाग व सीबीआई का विपक्षी पार्टियों के नेताओं को प्रताड़ित करने में जिस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, वह भी इन पार्टियों को एक साथ लाने में मददगार होगा। हाँ, सभी को कुछ खोने और कुछ पाने के लिए तैयार रहना होगा। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, विशेषकर राहुल गाँधी और मल्लिकार्जुन खडगे, मिलकर चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी त्याग करने के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनावों में वे भले ही राज्य स्तरीय नेतृत्व को सभी पार्टियों के साथ सहयोग करने के लिए राजी न कर पाए हों लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा। राहुल गाँधी ने कहा है कि विपक्ष को एक रखने के लिए कांग्रेस कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है। उन्होंने बिलकुल ठीक कहा है कि आने वाला आम चुनाव केवल चुनाव न होकर वैचारिक युद्ध होगा।

राम पुनियानी

अभी ऐसा लग सकता है कि विभिन्न विपक्षी दल अलग-अलग दिशा में भाग रहे हैं। मगर सम्भावना यही है कि लोकसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही इंडिया गठबंधन की मज़बूत बना लिया जायेगा और वह भाजपा-आरएसएस की विघटनकारी राजनीति से मुकाबला करने में सक्षम हो जायेगा। बहुसंख्यकवादी राजनीति द्वारा जिस ढंग की नफरत फैलाई जा रही है वह प्रजातंत्र को लम्बे समय तक जीवित नहीं रहने देगी। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थाओं सहित राज्य तंत्र की विभिन्न संस्थाओं में हिन्दू राष्ट्रवादियों की घुसपैठ गंभीर चिंता का विषय है।

इन सारे मुद्दों पर विचार कर विपक्ष एक होगा, हम यह मान सकते हैं। और अगर वह एक हो गया तो चुनाव जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। चुनाव में विजय, देश को हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडा के चंगुल से निकलने की दिशा में पहला कदम होगा।

# संसदीय लोकतंत्र के काले दिन वापस...

कोई दोषी नहीं। कोई जिम्मेदार नहीं। भारत की संसद की किस्मत ही खराब है जो उसे अपने एक चौथाई सदस्यों को निलंबित कर अपना कामकाज चलाना पड़ रहा है। चूंकि ये सब पहले भी हो चुका है इसलिए मौजूदा संसद के पीठाधीश्वर के ऊपर आप कोई आरोप नहीं लगा सकते,ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकते हैं कि, इस बार संसद पहले से ज्यादा बधिर और असहिष्णु है। लोकतंत्र के लिए ये अच्छे लक्षण नहीं हैं। वर्ष 2023 संसदीय इतिहास में एक कुटिल व्यवहार के लिए सदा याद किया जाएगा।

संसद के प्रति मेरे मन में अपार आस्था है और हर भारतीय के मन में होना चाहिए,क्योंकि ये संसद ही है जिसे हम न सिर्फ लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं बल्कि हमारा यकीन है कि इसी मंदिर में की गयी प्रार्थनाओं से हम भारतीयों की तमाम कामनाएं पूरी होतीं है। दुर्भाग्य से यही संसद पहले बहरी हुई और अब निर्मम तथा असहिष्णु भी हो गयी। मौजूदा संसद अब तक अपने 100 सदस्यों के विरुद्ध निलंबन और निष्कासन की कार्रवाई कर चुकी है। राज्य सभा के 45 और लोकसभा के 33 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा चुका है।

देश की संसद कोई प्राइमरी की कक्षा नहीं है, लेकिन उसे प्राइमरी की कक्षा बना दिया गया है। संसद की कार्रवाई का संचालन करने वाले पीठाधीश्वर अब ईश्वर से भी ऊपर हो गए हैं। उनके मन में दया-धर्म बचा ही नहीं है। वे संसद में प्रतिरोध के लिए रत्ती भर गुंजाइश नहीं देना चाहते। सांसद में पहले भी हंगामे होते थे लेकिन सदन चलने वाले अंत तक हार नहीं मानते थे, उस समय संसद की कार्रवाई भी तब स्थगित की जाती थी जब की पानी सर के ऊपर न हो जाये, लेकिन आजकल तो संसद शुरू होते ही स्थगित हो जाती है। सांसदों को डाटने-फटकारने, मार्शल बुलाने का कोई मौक़ा ही इस्तेमाल नहीं किया जाता। पल भर में सांसदों के नामों की एक फेहरिस्त आती है और सभी को निलंबित करने का ऐलान कर दिया जाता है।

संसद द्वारा की जारही इस निर्मम कार्रवाई के बारे में टीका-टिप्पणी करने पर आपको अतीत की याद दिलाई जाएगी कि राजीव गांधी के काल में भी तो 63 सांसदों को निलंबित किया गया था ! यानि जो राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ वो ही सब मोदी के शासन काल में होना चाहिए अन्यथा सत्तारूढदल की नाक कट जाएगी ! ये तर्क-कुतर्क करने वाले नहीं जानते कि राजीव गाँधी के शासनकाल में सांसदों को मात्र एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार लोकसभा से जिन सांसदों को निलंबित किया गया है, उनमें से 30 संसद के पूरे शीतकालीन सत्र तक निलंबित रहेंगे। बाकी तीन- के. जयकुमार, विजय वसंत और अब्दुल खालिक को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है, इन तीनों पर स्पीकर के पोडियम पर चढ़कर नारेबाजी करने का आरोप है।

इसी तरह, राज्यसभा से जिन 45 सांसदों को आज सस्पेंड किया गया है, उनमें से 34 को पूरे सत्र और 11 को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है।

सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करना पीठाधीश्वरों का विशेषाधिकार है, उसे लेकर कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन जनता के पास ये अधिकार है कि वो अपने चुने हुए सांसदों के खिलाफ की गयी कार्रवाई पर अपना असंतोष जाहिर करे। दरअसल इस समय संसद को ध्वनिमत से चलने की कोशिश की जा रही है। सांसद में बहस-मुबाहिसे के लिए, प्रतिरोध के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो बोलेगा उसे

निलंबित कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता येन-केन रद्द कर दी जाएग। फिर खूब खटखटाते रहिये अदालतों के दरवाजे। ये सब प्रतिपक्ष के सांसदों के साथ हो रहा है। किसी सदन में सत्ता पक्ष के किसी एक संसद को निलंबित किया गया? पीठाधीश्वर अपने-अपने सदन के संरक्षक और मुखिया होते है और वे भूल गए हैं कि मुखिया, मुख जैसा होता है यानि खान-पान में एक। देश को रामराज की और ले जाने वाले लोग भूल गए कि-

मुखिआ मुखु सो चाहिऐ खान पान कहुँ एक।
पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित बिबेक।।

संसद में आजकल का परिदृश्य देखकर कोई भी सदन कि संरक्षकों कि विवेक पर सवाल खड़े कर सकता है। पिछले दिनों इसी संसद में चार युवाओं ने तानाशाही, बेरोजगारी और उत्पीड़न कि खिलाफ प्रदर्शन करने कि लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। यदि यही काम सदन के सदस्यों को करने दिया जाता तो कोई बाहरी व्यक्ति कोनों सदन में अनाधिकार प्रवेश कर सदन की गरिमा से खिलवाड़ करता? लेकिन इस विरोध प्रदर्शन को सदन की गरिमा और सुरक्षा से न जोड़कर साजिशों से जोड़ा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों कि मुद्दों पर सदन में और सदन के बाहर बात करने कि लिए कोई तैयार नहीं है।

सांसदों को निलंबित करना सदन कि संचालकों का विशेषाधिकार है इसलिए कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता ।सांसदों का निलंबन पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन सांसदों कि साथ लगातार निलंबन को औजार बनाया जाना चिंताजनक है। पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया है। आंकड़े देखें तो पिछले 10 साल में लोकसभा और राज्यसभा के 154 सांसद निलंबित हो चुके हैं चुके हैं। इसमें उन सांसदों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें एक से ज्यादा बार निलंबित किया गया था। गोदे मुरहारी और राजनारायण उन सांसदों में से हैं जिन्हें उनके आचरण कि लिए पूरे सत्र में निलंबित रखा गया था। लेकिन अब ये अतीत भी बहुत पुराना हो गया है। इसकी यादें धूमिल पड़ चुकी हैं।

आपको याद होगा कि संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में सदन में हंगामे के कारण विपक्षी दल के सांसदों के खिलाफ कदम उठाया गया। र्ध्धानमनतरि और गृहमंत्री सदन में इस मुद्दे पर कोई ब्यान नहीं दे रहे जबकि सदन के बाहर वे सब कुछ कह रहे है। इन दोनों का आचरण संसद की गरिमा और विशेषाधिकार के खिलाफ नहीं माना जाता। सामूहिक निलंबन के बाद विपक्ष को दोहरा झटका लगा है। एक तो उनके सांसद सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे इसके अलावा लोकसभा में इंडिया गठबंधन की ताकत 50 फीसदी तो राज्यसभा में 33 फीसदी कम हो जाएगी। और यही सत्तारूढ़ दल का असल मकसद है। कल्पना कीजिये की यदि 303 सीटें हासिल करने वाली पार्टी का अभी ये हाल है और यदि खुदा न खास्ता इसी दल को 400 सीटें मिल जाएँ तो संसद का क्या हाल होगा? बहुमत का इतना दुरूपयोग तो राजीव गांधी ने भी नहीं किया था जबकि उनके दल को उस समय 404 सीटें मिलीं थीं।

राकेश अचल

अगले कुछ महीनों में शायद फरवरी में ही देश में लोकसभा कि नए चुनाव होना हैं इसलिए ये मौक़ा है की देश की जनता उसे चुने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कि खिलाफ न हो, जो असहिष्णु न हो, जो संसद को बहरा न बनाये। मर्जी है आपकी, क्योंकि वोट है आपका। हम तो वाच डॉग भर है। सावधन करना, जागते रहो ! की आवाज लगना हमारा काम है, सो हम कर रहे हैं।

# एक नजर लोकसभा सीट पर...

## 16 चुनावों में 3 बार महिला प्रत्याशी, तीनों बार कांग्रेस से नटराजन

माही की गूंज, मंदसौर। साहिल अगवान

*मंदसौर लोकसभा सीट 1951 से अस्तित्व में आई और लगभग 73 वर्ष हो चुके हैं। जानकर हैरत होगी कि, अब तक हुए 17 चुनाव में डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय के अलावा सुधीर गुप्ता को दोबारा सांसद चुना गया है। गुप्ता 2014 में जीतकर सांसद रहे फिर 2019 में जीतकर सांसद बने। यूं तो कई नेता 2 से 3 बार भाग्य आजमा चुके हैं लेकिन अधिकतम 1 बार ही जीत पाए तो कुछ का खाता नहीं खुला। डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय के बाद सुधीर गुप्ता ही दोबारा सांसद बने है।*

### 16 चुनावों में 3 बार महिला प्रत्याशी, तीनों बार कांग्रेस से नटराजन

मंदसौर सीट से 16 चुनाव में अब तक 3 बार प्रमुख राजनीतिक दलों ने महिला प्रत्याशी दिए हैं। तीनों बार कांग्रेस से मीनाक्षी नटराजन को टिकट मिला है जिसमे 2009, 2014 के बाद अब 2019 में नटराजन ने टिकट की हैट्रिक की मगर जीत नहीं पाई। 1951 से लेकर 2019 तक भारतीय जनसंघ-लोकदल व भाजपा से पुरुष प्रत्याशी रहे हैं। मंदसौर सीट कई बार बड़े उलटफेर व चौंकाने वाले नतीजे देने के लिए ख्यात रही है। इस संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा की सीटे है।

### इस बार दोनों तरफ से चेहरा बदलने की संभावना

वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता जिस प्रकार से विधानसभा में अपनी दावेदारी जता रहे थे उससे कहीं न कहीं लोकसभा में भाजपा की ओर से चेहरा बदलने की सम्भावना नज़र आ रही है। मगर सांसद सुधीर गुप्ता दावेदारों की दौड़ से कहीं बाहर नज़र नही आ रहे हैं। बल्कि प्रमुख दावेदारों की गिनती में है। अगर भाजपा चेहरा बदलती हैं तो अगला उम्मीदवार मंदसौर, गरोठ या मनासा विधानसभा से हो सकता है। अगर मंदसौर विधानसभा की बात करें तो किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया, पूर्व जिला अध्यक्ष मदनलाल राठौर नज़र आ सकते हैं। मनासा विधानसभा से कैलाश चावला, गरोठ विधानसभा से पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़ पर मोहर लग सकती है। अगर युवा चेहरे की बात करे तो गरोठ विधानसभा से पूर्व युवा मोर्चा उपाध्यक्ष विनित यादव और मंदसौर से जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया भी मैदान में नज़र आ सकते है। वहीं 2019 कांग्रेस भारी मतों से हारने के बाद यह से नए चेहरे पर दाव खेल सकती हैं।

**1951 से लेकर अब तक निर्वाचित सांसद**

| चुनावी वर्ष | विजयी प्रत्याशी | राजनीतिकदल |
|---|---|---|
| 1951 | कैलाशनाथ काटजू | कांग्रेस |
| 1957 | माणकभाई अग्रवाल | कांग्रेस |
| 1962 | उमाशंकर त्रिवेदी | भारतीय जनसंघ |
| 1967 | स्वतंत्रसिंह कोठारी | भारतीय जनसंघ |
| 1971 | डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय | भारतीय जनसंघ |
| 1977 | डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय | भारतीय जनसंघ |
| 1980 | भंवरलाल नाहटा | कांग्रेस |
| 1984 | बालकवि बैरागी उर्फ नंदराम दास | कांग्रेस |
| 1989 | डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय | भाजपा |
| 1991 | डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय | भाजपा |
| 1996 | डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय | भाजपा |
| 1998 | डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय | भाजपा |
| 1999 | डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय | भाजपा |
| 2004 | डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय | भाजपा |
| 2009 | मीनाक्षी नटराजन | कांग्रेस |
| 2014 | सुधीर गुप्ता | भाजपा |
| 2019 | सुधीर गुप्ता | भाजपा |

### मिशन 2024 में गरोठ विधानसभा की किस के हाथ में होगी बागडोर...?

गरोठ विधानसभा से पूर्व मंत्री की हार के बाद अब मिशन 2024 की गरोठ विधानसभा की कमान कौन संभालेगा...? कोन होगा कांग्रेस लोकसभा प्रत्याक्षी का सिपासलार...? गरोठ विधानसभा में कई चेहरे किसी के हाथ में होगी कमान...? यह भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। जिस पर पार्टी की ओर से अब तक कोई संकेत नही निकल कर सामने आए है।

# हिस्ट्रीशीटर बदमाश से भारी मात्रा में अफीम, डोडाचूरा, एमडी ड्रग और अवैध हथियार बरामद

माही की गूंज, रतलाम।

जिले की जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर बदमाश को भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। मंगलवार को एसपी राहुल लोढा ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी राहुल लोढा द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हुए हैं। जावरा आईए थाना प्रभारी ओपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध डोडाचूरा, अफीम, एमडी और हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

एसपी राहुल लोढा ने बताया कि, पुलिस को सूचना मिली कि हसनपालिया निवासी फजूल उर्फ अली हुसैन 38 वर्ष जीप से मादक पदार्थ लेकर रतलाम की तरफ जा रहा है। सूचना पर जावरा आईए की पुलिस टीम ने घेराबंदी कर जीप को रोका। पुलिस ने जीप चालक फजूल उर्फ अली हुसैन को हिरासत में लेकर वाहन की तलाशी ली तो उसमें 62 किलोग्राम डोडा चूरा, 2 किलो 800 ग्राम अफीम, 140 ग्राम एमडी, दो 12 बोर की लोडेड बंदूक, एक जिंदा कारतूस, 26 हजार 400 रुपए नगद बरामद किए गए।

एसपी राहुल लोढा ने बताया कि, आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में 10 के लगभग अपराध दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ सफेमा के तहत भी कार्रवाई होगी। इसमें संपत्तियों को भी अटैच किया जाएगा।

# शादी का झांसा देकर युवक ने नाबालिग का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, आरोपी को २५ वर्ष का सश्रम कारावास

माही की गूंज, नीमच।

जिले में 15 वर्ष की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। इस मामले में सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश सुशांत हुद्दार ने बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पाणदा गांव निवासी मोहन के बेटे आरोपी राजू (20) को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 363 के अंतर्गत तीन साल का सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड, धारा 366 के अंतर्गत पांच वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 376 (3) के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने बताया कि, 28 अप्रैल 2021 को पुलिस थाना नीमच सिटी क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने रिपोर्ट लिखवाई की थी कि 21 अप्रैल 2021 को उसकी 15 वर्ष की बेटी रात के लगभग साढ़े 8 बजे घर से यह कहकर निकली कि वह जरूरी काम से जा रही है। लेकिन रात के 10 बजे तक वापस नहीं आई। शंका के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। आरोपी पर अपराध क्रमांक 215/2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

### पीड़िता ने पुलिस को बताई आपबीती

पांच मई 2021 को पीड़िता पुलिस थाना नीमच सिटी में उपस्थित हुई। जहां पर उसने बताया कि आरोपी शादी करने का झांसा देकर अपहरण करके ग्राम डोरिया, निंबाहेड़ा (राजस्थान) ले गया था। जहां आरोपी ने उसे खुले मैदान में रखा और कई बार दुष्कर्म किया। रिपोर्ट के आधार पर जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर और पीड़िता का मेडिकल कराया गया। फिर पीड़िता की उम्र से संबंधित जरूरी सबूत इक्टठा कर जांच पूरी कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), नीमच में पेश किया गया। जहां सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई।

# शहर में शुरू हुई ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की कवायद

## ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शुरू ई चालान की कार्यवाही, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी

माही की गूंज, रतलाम।

शहर के कई हिस्सों में अब ट्रैफिक रूल तोड़ने का बड़ा खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ सकता है। शहर की लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था को पुलिस ने अब सुधारने का काम शुरू कर दिया और पुलिस अलर्ट मोड़ पर आ गई है। ट्रैफिक को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए पुलिस अब ''ई चालान'' की कार्यवाही करने जा रही है। यातायात सहित अनेक मुद्दों पर पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने प्लान बनाया है। पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने बताया कि, शहर में लगभग अनेक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके है। यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस अब ''ई चालान'' की कार्यवाही करने जा रही है। ''ई चालान'' सीधे लोगो के घर पर पहुंचेगा और न्यायालय में चालान की राशी जमा की जाएगी। एसीपी लोढ़ा ने बताया की शहर में सबसे पहले दो बत्ती पर ''ई चालान'' का काम किया जायेगा उसके बाद हर सप्ताह दो चौराहे को चिन्हित कर ''ई चालान'' की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जायेगा। इस दौरान एसपी लोढ़ा ने मीडिया के माध्यम से सीसीटीवी रूम में अपना ''ई चालान'' की कार्यवाही का प्लान बताया और ''ई चालान'' कैसा होगा उसकी भी जानकारी दी।

यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिये शहर के अलग-अलग स्थानों पर सब्जी व फल फ्रूट विक्रेताओ के लिए भी स्थान चिन्हित किये गए है। शहर में अब तीन स्थानों पर सब्जी बेचने वालो को स्थानांतरित किया जायेगा। पूर्व में भी सब्जी व फल फ्रूट विक्रेताओ को स्थान चिन्हित कर जगह दी गई थी परन्तु अमले ने इस पर ध्यान नहीं दिया जिससे सब्जी व फल फ्रूट विक्रेता जहा जगह मिली वही पर अपनी दूकान संचालित कर देते है।

# पांच वर्ष पहले मारपीट की, अब मिला 6 माह का कारावास

माही की गूंज, मंदसौर।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निकिता वार्ष्णेय मंदसौर द्वारा आरोपी विपिन पिता मनोहरलाल गोदा 49 वर्ष निवासी जनकुपुरा मंदसौर को मारपीट करने का दोषी पाते हुए 6 माह के कठोर कारावास और 2 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। अदालत ने यह फैसला पांच वर्ष पुराने एक मामले में दिया है।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि, 31 अक्टूबर 2018 को फरियादी राजेश ने आरोपी विपिन गोदा की स्कूटी रिपेयरिंग की थी। जिसके 1500 रूपये आरोपी विपिन गोदा से लेना थे। जब फरियादी राजेश आरोपी विपिन से पैसे मांगने के लिये उसकी दुकान पर गया तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौच कर मारपीट की, जिससे फरियादी राजेश की उंगली फ्रेक्चर हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना शहर कोतवाली मंदसौर पुलिस द्वारा प्रकरण में कार्यवाही कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

# जिले के आशुतोष शर्मा दिखेंगे आईपीएल में, उज्जैन सम्भाग के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बने आशुतोष

## पंजाब किंग्स ने बेस प्राइस पर खरीदा

माही की गूंज, रतलाम।

क्रिकेट का महासमर इंडियन क्रिकेट लीग आईपीएल अब छोटे शहरों की प्रतिभाओं को मंच देने का बड़ा स्थान बन चुका है। कई युवा क्रिकेटर आईपीएल में अपने प्रदर्शन के दम पर देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। साथ ही आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जगह मिलने और अच्छा प्रदर्शन करने पर बड़ी राशि खिलाड़ियों को मिल रही है। रतलाम से निकले होनहार क्रिकेटर आशुतोष शर्मा भी अब इस बड़े मंच पर दिखाई देंगे। आशुतोष शर्मा के भाई अनिल शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि, आशुतोष वर्तमान में रेलवे की टीम से खेलते हैं। पूर्व में वह मध्य प्रदेश रणजी टीम के साथ भी खेल चुके हैं। आशुतोष रतलाम और उज्जैन संभाग से पहले आईपीएल खेलने वाले प्लेयर होंगे। आशुतोष शर्मा ने रतलाम के रेलवे ग्राउंड और आरपीएफ ग्राउंड पर क्रिकेट खेलना शुरू किया था और क्रिकेट कोच भूपेंद्र सिंह चौहान और लोकपाल सिंह सिसोदिया की कोचिंग में खेलते हुए मध्य प्रदेश रणजी टीम और बाद में रेलवे की टीम में जगह बनाई। बीते दिनों ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 20-20 मैच में रेलवे की तरफ से खेलते हुए आशुतोष शर्मा ने ताबड़तोड़ अर्द्ध शतक लगाया था। यही वजह रही कि आईपीएल ऑक्शन में आशुतोष शर्मा के नाम को शामिल किया गया और पंजाब किंग्स की टीम ने उन्हें 20 लाख रुपए मूल्य की बेस प्राइज पर खरीदा है।

# चाइना डोर से हुए हादसे के बाद जागा प्रशासन, चलाया सर्चिंग अभियान

माही की गूंज, शाजापुर।

चाइना डोर की चपेट में आने से बीते दिनों एक शख्स का गला श्वास नली तक कट गया था। गंभीर घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चाइना डोर से बढ़ते मामलों के बाद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है कि, बाजार में चाइना डोर न बिके न लोग इसे खरीदे।

पुलिस ने चाइना डोर को लेकर शहर में सर्चिंग अभियान चलाया। लेकिन इस दौरान किसी भी दुकान पर चाइना की डोर नहीं मिली। लेकिन दुकानदारों को सख्त हिदायत जरूर दी गई है कि यदि वे चायना डोर बेचते पाए गए तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जवानों ने शहर की कई दुकानों की जांच की और सभी को समझाइश दी।

बता दें कि, शहर में अभी भी बड़े पैमाने पर चाइना डोर की बिक्री चोरी छिपे हो रही है। दिसंबर से लेकर जनवरी तक चाइना डोर से जख्मी होने के मामले बड़ी संख्या में जिला अस्पताल में आते हैं।

### पुलिस की चाइना डोर के मामलों ने नींद उड़ाई

पतंगबाजी में उपयोग होने वाली चाइना की डोर बेहद ही नुकसानदायक होती है, जहां यदि यह डोर किसी के गले या शरीर के किसी अंग में फंस जाए तो उस अंग को काट देती है। यही कारण है कि, पतंगबाजी के लिए उपयोग होने वाली चाइना की डोर को प्रतिबंधित करने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। शहरवासियों का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद चाइना डोर की बिक्री हो रही है। इनकी बिक्री पर जिला प्रशासन रोक नहीं लग पा रहा। चाइना डोर बेचने, उपयोग करने, खरीदने और भंडारण करने पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं इन बढ़ते मामलों ने पुलिस की नींद भी उड़ा दी है।

### चायना डोर के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध

पतंगबाजी में चाइना डोर के उपयोग से आम जनता एवं पशु-पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए कलेक्टर किशोर कन्याल ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत चाइना डोर के उपयोग एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार शाजापुर जिले में कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी के दौरान चीन में बनी चायना डोर का उपयोग एवं संग्रहण नहीं करेगा। दुकानों पर चीन में बनी चायना डोर न तो विक्रय के लिये रखी जायेगी और न ही उसका विक्रय किया जायेगा।

### बाजारों में सजने लगी पतंग और डोर की दुकान

संक्रांति 14 और 15 जनवरी को मनाई जाएगी, ऐसे में पतंगबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बाजारों में पतंग और डोर की दुकान सज गई है और आसमानों में पतंगे भी नजर आने लगी है ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी चाइना डोर बाजार में आ गई है, जिससे होने वाले हादसे भी सामने आने लगे हैं। इन दिनों पतंग और डोर बेचने वालों की दुकानें सज जाती है, वही अब पतंगे भी आसमान में दिखाई देने लगी है।

# मालदीव से लौटे एक ही परिवार के 2 लोग हुए कोविड संक्रमित

**इंदौर।** मालदीव की यात्रा के बाद अपने गृहनगर इंदौर लौटे एक परिवार के दो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनके नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, ताकि कोरोना वायरस से प्रकार का पता लगाया जा सके। यह जानकारी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) की इंदौर जिला इकाई के नोडल अधिकारी डॉ. अमित मालाकार ने बुधवार को दी।

उन्होंने बताया कि, इस वायरल बीमारी से एक ही परिवार की 33 वर्षीय एक महिला और 38 वर्षीय एक पुरुष संक्रमित हुए हैं। देश में कोविड-19 के नए जेएन.1 वैरिएंट के सामने के साथ कुछ राज्यों में वायरल संक्रमण में वृद्धि हो रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी इंदौर में भी कोरोना का मामला सामने आया है।

डॉ. अमित मालाकार ने बताया कि, पलासिया क्षेत्र की रहने वाली महिला 13 दिसंबर को कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद से उसने होम आइसोलेशन में सात दिन पूरे कर लिए हैं। वहीं, पुरुष में संक्रमण का पता 18 दिसंबर को चला था। वह अभी भी होम आइसोलेशन में रह रहे हैं।

मालाकार ने कहा कि, दोनों मरीज करीबी रिश्तेदार हैं और कुछ दिन पहले ही मालदीव से घूमकर लौटे हैं। इनमें सर्दी-खांसी के लक्षण पाए गए थे। फिलहाल दोनों की हालत ठीक है। दोनों मरीजों के नमूने भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में पूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे कोरोना वायरस के किस वैरिएंट से संक्रमित हुए हैं।

### 8 दिसंबर को मिला नया वैरिएंट जेएन.1

देश में कोविड-19 का नया वैरिएंट जेएन.1 का पहला मामला 8 दिसंबर को केरल में सामने आया था। केंद्र सरकार ने आम जनता से बंद स्थानों में, खासकर ठंडे मौसम के दौरान और नए साल के जश्न में भीड़ की आशंका को देखते हुए एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले कहा था कि उनकी सरकार ने कोविड-19 के नए संस्करण के संबंध में केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लागू किया है।

# ग्रामीणों ने हाथ उठाकर लिया विकसित भारत का संकल्प, यात्रा पहुंची ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग

**माही की गूंज, बड़वानी।**

विकसित भारत संकल्प यात्रा हेतु भारत सरकार के नोडल अधिकारी अरविन्द कुमार एमके एवं प्रभारी कलेक्टर जगदीश कुमार गोमे बुधवार को ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग पहुंचे। ग्राम में पहुंचते ही उनका स्वागत एवं अभिवादन ग्राम की बालिकाओं एवं स्व सहायता समूह की दीदीयों ने तिलक लगाकर तो एनसीसी के बच्चों ने तालियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंतसिंह पटेल ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही ग्रामीणों को प्राकृतिक खेती एवं नैनो यूरिया के लाभ भी बताये।

प्रभारी कलेक्टर जगदीश कुमार गोमे ने संबोधित करते हुए कहा कि, सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाना ही यात्रा का उद्देश्य है। अतः पात्रतानुसार विभागीय अधिकारी ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देकर लाभ प्रदाय करें। जो योजनाएं लक्ष्य एवं मांग पर आधारित है, उन योजनाओं को छोड़ते हुए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से छूटे हुए पात्र हितग्राही को शिविर में ही लाभ देने का प्रयास किया जाये। कबीर पंथी भजनों का हुआ आयोजन विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग में ग्राम के वृद्धजनों ने धरती कहे पुकार के थीम के तहत कबीर पंथी भजनों की प्रस्तुति दी। जिसने सभी का मन मोह लिया। वहीं स्कूली बालिकाओं के द्वारा सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। हितग्राहियों ने सुनाई अपनी कहानी अपनी जुबानी कार्यक्रम के दौरान केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्राकृतिक खेती योजना पर अपनी कहानी अपनी जुबानी के तहत हितग्राहियों ने उन्हे किस प्रकार योजना का लाभ मिला इस बारे में विस्तार से ग्रामीणों को बताया।

यात्रा स्थल पर महिलाओं को वितरित किये गये गैस कनेक्शन ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भारत सरकार के नोडल अधिकारी अरविन्द कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंतसिंह पटेल, प्रभारी कलेक्टर जगदीश कुमार गोमे, जनपद सदस्य मोहनलाल मुलेवा एवं ग्राम की सरपंच श्रीमती मंजुला मुजाल्दे ने प्रधानमंत्री उज्वला गैस योजनान्तर्गत ग्राम की श्रीमती सुमन बाई सोहन, श्रीमती लक्ष्मी दशरथ चौहान तथा श्रीमती कविता नंदराम सेंगर को गैस चूल्हा एवं गैस सिलेण्डर सहित अन्य सामग्री का वितरण किया। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत कैलाश धन्नलाल चौहान, गोपाल दूधाजी, रोहित दिनेश चौहान को अनाज का वितरण किया गया। वहीं ग्राम की स्व सहायता समूह की महिलाओं को 3 लाख रुपये के ऋण का भी वितरण किया गया। किया गया प्रमाण पत्रों का वितरण कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली बालिकाओं तथा ग्राम में प्राकृतिक खेती करने वाले कृषक मोहनलाल अगलचा को भी प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया। ग्रामीणों ने हाथ उठाकर लिया विकसित भारत का संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान प्रभारी कलेक्टर जगदीश कुमार गोमे ने सभी को विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया। इस दौरान ग्रामीण महिला, पुरूषों, युवाओं एवं बच्चों ने अपने हाथ उठाकर 2047 तक भारत देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प भी लिया।

# जिला खेल परिसर का खिलाड़ी करेगा हाकी टीम का प्रतिनिधित्व

**माही की गूंज, बड़वानी।**

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 67 मिनी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो कि ग्वालियर शहर में दिनांक 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक आयोजित होगी। जिसमें खेल परिसर बड़वानी के खिलाड़ी अजय नीमला सोलंकी करेंगे मध्य प्रदेश मिनी हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। अजय का चयन लोक शिक्षण संचनालय भोपाल द्वारा आयोजित स्टेट हॉकी चैंपियनशिप मंदसौर में किए गए अच्छे प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। हॉकी कोच मुकेश राठौर ने बताया कि अजय मूलतः ठेंचा (पाटी) गांव का निवासी है माता-पिता कृषि करते हैं विगत 3 वर्षो से अजय बड़वानी के खेल परिसर में रह रहा है एवं हॉकी खेल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। प्री नेशनल कोचिंग कैंप 22 से 3 जनवरी तक ग्वालियर के राज्य महिला हॉकी अकादमी मे आयोजित कैंप में प्रदेश की टीम मे सम्मिलित होगा पश्चात टीम राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इस उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत, सहायक आयुक्त विवेक गुप्ता, प्राचार्य इकबाल आदिल, क्रीड़ा प्रभारी मुकेश मालवीय एवं जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष अमृतलाल अग्रवाल एवं समस्त पदाधिकारी एवं खिलाड़ियों ने हर्ष व्यक्त किया।

# कंपकंपी वाली ठंड से जूझ रहे लोगों की बारिश बढ़ाएगी टेंशन

**भोपाल।**

मध्य प्रदेश में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से प्रदेश के कई शहर ठंड की चपेट में हैं। कई जिलों में बर्फीली हवाओं से 10 डिग्री सेल्सियस पारा चल रहा है। वहीं 20 के करीब शहर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। ऐसा ही सीजन में पहली बार हुआ है जब भी से अधिक शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी हुई थी और अब बर्फ पिघल रही है। ऐसे में वहां से आ रही हवा में ठंडक घुल गई है। इस वजह से प्रदेश में दिन-रात के तापमान में गिरावट हो रही है। आने वाले दो से तीन दिन तक मौसम का असर ऐसा ही रहेगा।

उज्जैन शहर में मंगलवार बुधवार की दरम्यानी रात न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री कम होकर 10 डिग्री पर पहुंच गया। जिससे पूरी रात कड़ाके की सर्दी से लोग जूझते रहे और अलाव तापते नजर आए। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस था। उत्तर भारत में बर्फबारी होने और बर्फीली सर्द हवा आने के कारण मौसम में अचानक से ठंडक बढ़ी है। दो-तीन दिन के भीतर एक पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय होगा, जिससे मौसम में सर्दी का असर बढ़ेगा। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य औसत तापमान से 4.8 डिग्री सेल्सियस कम है। इधर रात में तापमान कम होने से ठिठुराने वाली सर्दी बनी हुई है।

दतिया, ग्वालियर, पचमढ़ी में सबसे सर्द रात रही तो उज्जैन, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में तापमान 10 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री तक रहा। इंदौर में तापमान 11.6 डिग्री रहा तो दतिया में 6.4 डिग्री रहा। इसके अलावा रीवा में 6.5, राजगढ़ में 6.6, बैतूल और रायसेन में 7 डिग्री के करीब पारा चल रहा है। दामोह छिंदवाड़ा सिवनी में पारा 9 डिग्री से 9.7 डिग्री तक मापा गया। मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर-लद्दाख के पास वेस्टर्न डिस्टरबेंस मौजूद है। यह मध्यप्रदेश के मौसम को भी प्रभावित कर रहा है। 22-23 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश का भी अनुमान बताया जा रहा है। वहीं राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में चक्रवाती हवा के घेरे का असर प्रदेश में पड़ा है। इस वजह से शनिवार से मौसम बदला है। इस घेरे के कारण अरब सागर से नमी आई तो मौसम में हुए बदलाव के कारण दिन में फिर ठंडक बढ़ गई है।

# 95 लाख से अधिक के चेक बाउंस मामले में आरोपी बरी

## प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय जैन ने सुनाया फैसला

**माही की गूंज, बड़वानी।**

वैध ऋण राशि के भुगतान या अन्य वैधानिक दायित्व हेतु चेक प्रदान करने की बात साबित नहीं कर पाने पर आरोपी को दोषमुक्त किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनय जैन ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी का दोषमुक्त कर दिया।

प्रकरण में पैरवी करने वाले अधिवक्ता सुश्री जया शर्मा ने बताया कि परिवादी नरेंद्र सोलंकी ने ग्राम बावड़ीमापी निवासी ने सागर सिंह पर सरकारी नौकरी के नाम पर रुपए ऐंठने का आरोप लगाते हुए 95 लाख 80 हजार रुपये का चैक बाउंस केस न्यायालय में लगाया था। इस पर आरोपी की अधिवक्ता ने परिवादी की आर्थिक स्थिति को न्यायलय के सामने रखते हुए नकद राशि भुगतान का कोई सबूत नहीं होने संबंधी तथ्य न्यायालय में प्रमाणित किया। साथ ही परिवादी चेक में दर्शाई गई राशि किसी वैध विधिक संव्यवहार या ऋण राशि के भुगतान दायित्व के परिणाम स्वरूप चैक प्रदान करने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं कर पाया। इस आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद खारिज करते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

# अब मंडी में कपास नीलामी का कार्य दोपहर 3 बजे तक होगा

**माही की गूंज, खरगोन।**

केन्द्र प्रभारी भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) खरगोन के आवेदन अनुसार कपास का पंजीयन एवं किसान का बिल बनने मे सॉफ्टवेयर समस्या के कारण 19 दिसंबर से कपास मंडी में कपास की नीलामी का कार्य प्रारंभ होने से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। विक्रय किये कपास की तुलाई का कार्य उसी दिन शाम 6 बजे तक होगा। शेष विक्रय किये वाहनों का तुलाई का कार्य अगले दिवस मे किया जाएगा। वहीं भारतीय कपास निगम सीसीआई द्वारा प्रत्येक शनिवार को कपास खरीदी बन्द रहेगी। व्यापारियों की कपास की खरीदी पूर्ववत् शाम 5 बजे तक चालु रहेगी।

# सीएम राइज विद्यालय टेमला में वार्षिक उत्सव का हुआ आयोजन

**माही की गूंज, खरगोन।**

सीएम राइज विद्यालय टेमला में वार्षिक उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। जिसमें तीन दिवसीय वार्षिक उत्सव में खेल के साथ रंगोली, पेंटिंग, मेहंदी प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छात्र-छात्राओं ने यह बता दिया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है उसे अवसर का इंतजार होता है। छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रभारी संतोष जायसवाल एवं सुश्री साधना सक्सेना के मार्गदर्शन में संपन्न हुए। कार्यक्रम के अंत में छात्रपरिषद एवं हाउस पदाधिकारियों की बेज शेरेमनी के साथ शपथविधि कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि प्रशांत आर्य सहायक आयुक्त ने कहा कि, विद्यार्थियो से जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उस और कड़ी मेहनत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि, परिणाम की चिंता न करे परिणाम हमारी मेहनत का मिलेगा। इस अवसर पर विशेष अतिथि शिक्षाविद दिलीप करपे एवं भागीरथ पाटीदार तथा जिलाध्यक्ष शिक्षक संघ रमेश चंद्र पाटीदार, प्राचार्य अशोक सिंह पवार सहित विद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

# राज्यसभा सांसद डॉ. सोलंकी ने केंद्रीय रेल मंत्री की मुलाकात

**माही की गूंज, बड़वानी।**

राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल एवं दूरसंचार मंत्री से की मुलाकात राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि, उन्होंने केंद्रीय रेल एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य भेंटकर पश्चिम निमाड़ क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित इंदौर-मनमाड़ रेल मार्ग परियोजना की मंजूरी उपरांत शीघ्र कार्य प्रारंभ करने तथा जनजातीय क्षेत्र में आवागमन एवं संचार साधनों का विस्तार करने को लेकर पत्र सौंपकर आग्रह किया। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पाटीदार भी उपस्थित रही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों विषयों पर उचित निराकरण करने के लिए आश्वस्त किया।

# तीन दिवसीय सक्षम प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

**माही की गूंज, बड़वानी।**

जनजातीय कार्य विभाग एवं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में 16 से 18 दिसम्बर तक चार वर्षीय जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम ÷सक्षम÷ के माध्यम से 21वीं सदी के जीवन कौशलों को विकसित करने के लिए, किया जा रहा है, ताकि वे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके। रोजगार पूरक कौशल शिक्षा के माध्यम से युवा किशोरों को रोजगार प्राप्ति के लिए तैयार किया जा सके। स्थानीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़वानी में आयोजित तीन दिवसीय सक्षम प्रशिक्षण में 50 माध्यमिक शिक्षकों का प्रथम बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा पर गतिविधि आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक सीख, संवाद, समानुभूति स्व जागरूकता जैसे जीवन कौशलों विषयों पर केन्द्रित था। प्रशिक्षकों ने विभिन्न खेलों के माध्यम से बच्चों को दी जाने सीखो के बारे में जानकारी दी। प्रायोगिक और सैद्धांतिक पहलुओं के माध्यम से प्रशिक्षण में शिक्षकों को गुर सिखाए गये ताकि वह अपनी शालाओं में बच्चों को व्यवहार परिवर्तन के साथ अन्य गुण भी विकसित कर सकें। फाउंडेशन की विकासखंड प्रबंधक लीना घोषी बड़वानी, मीनाक्षी यादव निवाली एवं सचिन कुमरावत पाटी से मास्टर ट्रेनर सुरेन्द्र पाटीदार, संतोष पटेल एवं बापूसिंह बघेल द्वारा प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया गया। प्रशिक्षण को सफल बनाने में जनजातीय कार्य विभाग एवं विकासखंड शिक्षा कार्यालय बड़वानी से ए.आर.मुजाल्दे प्र.सहायक आयुक्त के मार्गदर्शन एवं विकास खण्ड शिक्षा बड़वानी के कार्यालयीन कर्मचारी मुकेश मण्डलोई, मांगीलाल यादव, अमित सोलंकी, यशपाल यादव एवं महेन्द्र कन्नौज का भी सराहनीय सहयोग रहा।


माही की गूंज
बेबाकी के साथ...
एजेंसी देना है
झाबुआ जिले में: रंभापुर, मदरानी, झकनावदा, खवासा, राणापुर
अलीराजपुर जिले में: सौंडवा, कट्ठीवाड़ा, छकतला, चांदपुर, बोरी
संपर्क - 9589882798, 9981318651


# विकसित भारत संकल्प यात्रा में पात्र हितग्राहियों को दिया जाये योजना का लाभ- नोडल अधिकारी

**माही की गूंज, बड़वानी।**

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का संचालन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ, वंछित वर्ग के नागरिकों को देना। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिस भी ग्राम में जाये, वहां पर यह सुनिश्चित किया जाये कि अगर कोई व्यक्ति पात्र है और किसी शासकीय योजना के लाभ से छूट जाये तो उसे शिविर स्थल पर ही योजना का लाभ दिया जाये। भारत सरकार से जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी अरविन्द कुमार एमके ने उक्त बाते बुधवार को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी के सभागृह में आयोजित बैठक के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्जवला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योना, नैनो उर्वरक योजना, स्वाइल हेल्थ कार्ड एवं उन्नत कृषि यंत्र योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि योजना में शतप्रतिशत लोगों को पात्रतानुसार लाभ अनिवार्य रूप से मिले। समीक्षा के दौरान उन्होने यह भी निर्देशित किया कि जिन ग्रामों में शिविरों का आयोजन होना है, वहां पर एक दिवस पूर्व ही ग्रामों में डोंडी पिटवाकर या अन्य किसी माध्यम से ग्रामीणों को सूचना दी जाये, जिससे कि उन्हे पता रहे कि कल ग्राम में शिविर का आयोजन होना है, जिससे कि वे योजना के अंतर्गत अगर छूटे हुए है तो अपने दस्तावेज साथ लेकर आये जिससे उन्हे योजना का लाभ मिल सके।

बैठक में प्रभारी कलेक्टर जगदीश कुमार गोमे ने विकसित भारत संकल्प यात्रा से संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपनी योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हेतु कार्य करें। साथ ही मैदानी अमले को भी निर्देशित करे कि वे ग्रामों का भ्रमण करे एवं नये पात्र हितग्राहियों को योजनाओ का लाभ देवे। अगर किसी विभाग की योजना के लिए बाद में कोई हितग्राही आकर कहता है कि उसे पात्रता होने के बाद भी योजना का लाभ नही मिला तो संबंधित विभाग के अधिकारी पर कार्यवाही की जायेगी। अतः अधिकारी एवं उनका अधीनस्थ मैदानी अमले सजकता एवं सर्तकता से ही कार्य करे। बैठक में अपर कलेक्टर केके मालवीय, एसडीएम बड़वानी शक्तिसिंग चौहान सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

# उज्जैन में शिप्रा शुद्धीकरण के लिए बनाएं प्रोजेक्ट

**माही की गूंज, उज्जैन।**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में प्रवाहित मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के जल की शुद्धि के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि कान्ह का गंदा पानी शिप्रा में न मिले, ये सुनिश्चित करें। निर्देश को अमल में लाने के लिए तत्काल भोपाल में अफसरों ने बैठक की। वर्चुअल रूप से उज्जैन के अधिकारी भी जुड़े। उपाय एक ही सुझाया कि, इंदौर-सांवेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की क्षमता बढ़ा दी जाए और उज्जैन में कान्ह नदी पर एसटीपी लगा दिया जाए।

बैठक में बताया गया कि, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का सीवेज युक्त पांच क्यूमेक प्रदूषित पानी कान्ह नदी के रूप में उज्जैन आकर शिप्रा नदी (स्नान क्षेत्र) में त्रिवेणी घाट के समीप मिल रहा है। इससे शिप्रा का समूचा स्वच्छ जल भी दूषित हो रहा है। ये मिलन रोकने को साल 2016 में 95 करोड़ रुपये खर्च कर कान्ह डायवर्शन पाइपलाइन योजना को धरातल पर उतारी थी मगर वो पूरी तरह सफल न हो पाई।

पिछले वर्ष 5 दिसंबर 2022 को जल संसाधन विभाग ने शिप्रा नदी के नहान क्षेत्र (त्रिवेणी घाट से कालियादेह महल तक) में कान्ह का पानी मिलने से रोकने को 598 करोड़ 66 लाख रुपये की कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना स्वीकृत की थी, जो

अगले कुछ महीनों में धरातल पर आकार लेती नजर आ जाएगी। मगर इतने पर भी शिप्रा शुद्ध नहीं होने वाली। क्योंकि क्लोज डक्ट परियोजना के क्रियान्वयन से केवल कान्ह का रास्ता बदलेगा। आगे जाकर वो शेष शिप्रा के शेष हिस्से का जल पूरी तरह प्रदूषित करती रहेगी। उपाय यही है शिप्रा में गंदा पानी मिलने ही न दिया जाए। इसके लिए 'इंदौर-सांवेर में एसटीपी की क्षमता बढ़ाना चाहिए। उज्जैन में राघोपिपल्या के आसपास कान्ह नदी पर एसटीपी लगाना चाहिए।

### कैबिनेट की बैठक में योजना हो सकती मंजूर

एसटी की योजना बनी तो इसे अगले माह उज्जैन में मकर संक्रांति (15 जनवरी) को प्रस्तावित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित करने, सवारी मार्ग चौड़ा करने, नानाखेड़ा से हरिफाटक पुल तक एलिवेटेड कारिडोर बनाने की योजना को भी स्वीकृति मिल सकती है।

### क्लोज डक्ट योजना की जिम्मेदारी वेंसर कंपनी को मिल सकती

इंदौर शहर की अगले 30 वर्ष की आबादी और सिंहस्थ- 2052 को ध्यान में रख जल संसाधन विभाग द्वारा बनाई 598 करोड़ 66 लाख रुपए की कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के क्रियान्यन की जिम्मेदारी हैदराबाद की वेंसर कंस्ट्रक्शन को मिल सकती है। इस कंपनी ने 15 प्रतिशत बिलो रेट पर काम करने का प्रस्ताव दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले तीन वर्ष में योजना पूरी हो जाएगी। 42 महीने में योजना पूरी करने का कार्य आदेश ठेकेदार फर्म को जारी होगा। निविदा शर्त अनुरूप तय ठेकेदार फर्म को अगले 15 वर्ष योजना का रखरखाव भी करना होगा। अब इंतजार मंत्रीमंडल के विस्तार होने और टेंडर को सक्षम स्वीकृति के लिए मंत्रियों के बोर्ड की स्वीकृति मिलने का है। स्वीकृति मिलते ही त्रिवेणी घाट के समीप गोठड़ा गांव में कान्ह पर पांच मीटर ऊंचा स्टापडेम बनाया जाएगा। यहां से कालियादेह महल के आगे तक 16.5 किलोमीटर लंबा एवं 4.5 बाय 4.5 मीटर चौड़ा आरसीसी बाक्स बनाकर जमीन पर बिछाया जाएगा। दावा है कि इस चोकोर बाक्सनुमा पाइपलाइन से कान्ह का 40 क्यूमेक पानी डायवर्ट किया जा सकेगा। अंतिम 100 मीटर लंबाई में ओपन चैनल का निर्माण किया जाएगा।

# जीतू पटवारी के समर्थकों पर दर्ज हुई एफआईआर...

**माही की गूंज, उज्जैन।**

महाकाल मंदिर में बिना अनुमति के प्रवेश करने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जीतू पटवारी महाकाल मंदिर बाबा का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। बिना अनुमति के कई लोगों ने महाकाल मंदिर के अंदर घुसने का प्रयास किया था। इस दौरान महाकाल मंदिर के गेट का कांच भी फूट गया था।

आरोप है कि, इस दौरान मंदिर समिति के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार भी किया गया। इसके बाद मंदिर समिति ने अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले को लेकर एसपी सचिन शर्मा का कहना है कि, मंदिर प्रशासक के द्वारा की गई शिकायत में 40-50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।

इसमें आरोप है कि उन्होंने बलपूर्वक मंदिर में प्रवेश करने और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। आवेदन के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर प्रकरण कायम किया गया है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी।

### 19 दिसंबर की दोपहर मंदिर में बलपूर्वक किया था प्रवेश

मंदिर प्रशासक ने पुलिस को बताया था कि, 19 दिसंबर की दोपहर लगभग 12 बजे 40 से 50 कार्यकर्ताओं ने मंदिर में उस जगह से प्रवेश किया था, जहां से नहीं करना चाहिए। इसके बाद बलपूर्वक जब उन्होंने जोर लगाया तो वहां की शासकीय संपत्ति को नुकसान हुआ। कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया।

आवेदन प्राप्त होने पर संदेह पाए जाने पर उनके ऊपर प्रकरण कायम किया गया है, क्योंकि कौन इसमें शामिल है, उसकी तस्वीर वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हो सकेगी। जल्द ही उनकी पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

# वैश्य समाज के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन

**माही की गूंज, आम्बुआ।**

मध्य प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता के निर्देशानुसार नव वर्ष 2024 के पंचांग कैलेंडर का विमोचन सभी जिला तथा तहसील मुख्यालय पर किया जाने का निर्देश प्राप्त होने के बाद वैश्य समाज के अलीराजपुर जिला अध्यक्ष राजेश जैन ने बताया कि, सामाजिक समरसता लाने के लिए वैश्य समाज के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन कर गांव-गांव तक पहुंचना है। इसी कड़ी में 17 दिसंबर को आम्बुआ वैश्य समाज की इकाई द्वारा कैलेंडर का विमोचन किया गया। जिसमें भरत महेश्वरी, संतोष गुप्ता, अनिल, गिरधर खंडेलवाल, गोविंदा, विशाल महेश्वरी, संतोष, निलेश, अंतिम, विकास राठौर, ऋषिकेश गुप्ता, अंशुल समरथलाल गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

# खुले में मांस-मछली विक्रय पर रोक, जारी हुए आदेश

**माही की गूंज, अलीराजपुर।**

जिला दंडाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी कर खुले में पशु मांस तथा मछली के क्रय-विक्रय को संपूर्ण जिले में प्रतिबंधित कर दिया गया है। जारी किए गए आदेश के बाद अवैध अथवा नियम विरूद्ध या बिना अनुज्ञप्ति (लायसेंस) के पशु मांस या मछली विक्रय कर शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत खुले में पशु मांस तथा मछली के क्रय-विक्रय को संपूर्ण जिले में प्रतिबंधित कर दिया गया है। जारी किए गए आदेश के तहत संबंधित दुकानदार के लिए अपनी दुकान के सामने अपारदर्शित कांच लगाना जाना आवश्यक होगा, इसके साथ ही संबंधित दुकानदार को अपनी दुकान में साफ-सफाई रखने एवं कचरे का निस्तारण नगरपालिका द्वारा चिन्हित स्थान पर किया जाना भी सुनिश्चित करना होगा। जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार विक्रेता को धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि के बाहर दुकान लगानी होगी। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया जाना पाया गया तो भारतीय दण्ड संहिता एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा। जारी आदेश के तहत नगरपालिका को निर्देशित किया गया है कि जिले में आवारा श्वानों की संख्या में वृद्धि तथा गंदगी फैलाने की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, अतः इसे नियंत्रित किया जाए।

# गोवंश पलकों की बेरुखी के कारण आवारा घूमने को मजबूर

## बाजारों से कचरा पन्नी खाकर असमय मरने को मजबूर

**माही की गूंज, आम्बुआ।**

आम्बुआ ही नहीं अपितु संपूर्ण अलीराजपुर जिले में शहरी तथा कस्बाई पशु पालक अपने पालतू पशुओं को विशेष कर गोवंशों को आवारा छोड़कर असमय मौत के मुंह में धकेल रहे हैं।

गोवंश को पालने वाले पशुपालक गौ माता को पालने लगते हैं मगर वह तब तक खूंटे से बांधते हैं जब तक दूध देते हैं इसके बाद बच्चों सहित छोड़ दिया जाता है दाना पानी की तलाश में आवारा भटकते रहते हैं। हिंदू सनातनी परिवारों में इन गायों तथा गोवंशों को घर में बनी पहली रोटी दी जाती है रोटी की लालच में गोवंश घरों घरों में भटकते हैं तथा बाजार में पड़ा कूड़ा कचरा पन्नी आदि खाकर पेट भरते हैं। कई बार उनके पेट में ऐसे पदार्थ चले जाते हैं जिससे इनका स्वास्थ्य खराब होता है और असमय मौत हो जाती है। आम्बुआ में भी ऐसे ही कई गोवंश काल के गाल में समा चुके हैं।

ताजा मामला 14 दिसंबर की रात का है जब एक नन्दी (बैल) बछड़ा जो मुश्किल से साल डेढ़ वर्ष का होगा अज्ञात बीमारी के चलते सार्वजनिक सुविधा घर (शौचालय) के बराड़े में मौत के मुंह में चला गया। सुबह जब लोगों ने देखा तो मोबाइल पर सूचना चली तब कहीं जाकर गोवंश मलिक का पता चला तथा पंचायत द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया गया। कई बार मरने वाले गोवंशों के मालिक का पता नहीं लगने पर परेशानी भी होती है।

# ग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ आयोजन

**माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।**

विकसित भारत संकल्प यात्रा जनपद पंचायत चन्द्रशेखर आजाद नगर की ग्राम पंचायत बड़ी करेंटी में आयोजित की गई। जिसमें भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की सफलता की जानकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के द्वारा वीडियो किल्प दिखाई गये। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष इंदरसिंह डावर ने शुभारंभ किया एव अपने उद्बोधन में भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी रविन्द्र गुप्ता, वरिष्ट कृषि विस्तार अधिकारी मानसिंह चंगोड़, पशुपालन अधिकारी मालसिंह खरत, खण्ड स्रोत समन्वयक राजेन्द्र बैरागी, डॉ. नागर ग्राम पंचायत सरपंच कलम बाई जमरा, सचिव रोजगार सहायक, स्वास्थ्य विभाग, जनपद पंचायत का स्टाफ त्तथा ग्रामीण जन उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड, सिकल सेल, सॉइल कार्ड का वितरण किया गया। ग्रामीणों द्वारा सेल्फी पाइंट पर फोटो भी खिंचवाए। तथा विकसित भारत स्कल्प यात्रा के टोपी, टीशर्ट, ब्रोच, पेम्पलेट, कैलेंडर भी वितरित किये गए।

# जिन पत्थरों को कुल देवता पूजा वे निकले डायनासोर के अंडे

**माही की गूंज, धार।**

जिले के पाड़लिया गांव में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। गांव वाले वर्षों से जिन पत्थरों को कुल देवता मानकर पूजा अर्चना कर रहे थे, वो करोड़ों वर्ष पहले के डायनासोर के अंडे निकले। दरअसल, नर्मदा घाटी का यह इलाका करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर युग से जुड़ा रहा है और यहां पर करीब 6.5 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर का क्षेत्र हुआ करता था। हालांकि, अब प्रशासन हरकत में आकर अंडों की जांच कर रहा है।

स्थानीय डायनासोर विशेषज्ञ विशाल वर्मा ने बताया कि, कुछ दिन पहले तीन वैज्ञानिकों का वर्कशॉप आयोजित किया गया था। इस वर्कशॉप में वैज्ञानिक डॉ. महेश ठक्कर, डॉ. विवेक वी कपूर, डॉ. शिल्पा आए हुए थे। ये सभी मांडू स्थित डायनासोर फॉसिल्स पार्क के विकास कार्य का जायजा लेने के लिए भी आए थे। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने देखा कि गांव के लोग करीब 18 सेंटीमीटर व्यास के गोल पत्थरों की पूजा करते हैं। एक जानकार ग्रामीण वेस्ता पटेल ने बताया कि, गोल पत्थरों में उनके काकर भैरव वास करते हैं। यह देव पूरे गांव पर कोई संकट नहीं आने देते हैं।

लखनऊ से आई वैज्ञानिकों की टीम ने जब जांच की तो पता चला कि, गोल पत्थरनुमा आकृति तो डायनासोर के अंडे हैं। इनकी गांव के लोगा देवता मानकर पूजा कर रहे थे।

# रासेयो का एक दिवसीय दिशा निर्देश कार्यक्रम सम्पन्न

**माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।**

शासकीय महाविद्यालय चन्द्र शेखर आजाद नगर (भाबरा) में झाबुआ-अलीराजपुर जिले के राष्ट्रीय सेवा योजना (रासेयो) के कार्यक्रम अधिकारियों का एक दिवसीय दिशा निर्देश कार्यक्रम आयोजित हुआ। मां सरस्वती और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की तस्वीर पर पूजन एवं माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। छात्राओं ने रासेयो लक्ष्य गीत प्रस्तुत किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एसएस डोडवे मने अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ व स्वागत उदबोधन से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व वक्ता डॉ. प्रकाश गढ़वाल, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर रहे। उन्होंने अपने वक्तव्य में विद्यार्थियों से कहा कि, राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक बनकर देश के विकास में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया है। रासेयो कार्यक्रम अधिकारियों को राष्ट्रीय सेवा योजना में किस प्रकार से विद्यार्थियों को जोड़ना, नियमित गतिविधियों का आयोजन विशेष शिविर के आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में अलीराजपुर जिले के रासेयो जिला संगठन डॉ. सुरेश तोमर, झाबुआ जिले के जिला संगठन डॉ. बीएल डावर व दोनों जिलों के रासेयो कार्यक्रम अधिकारी, डॉ. नवनीत सांकला, प्रो. मानसिंह डोड़वा महाविद्यालय स्टॉफ रासेयो वालंटियर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रो. कमलेश गणावा ने किया व आभार प्रो. निलेश परमार ने माना।

# गरीबों के हक पर पड़ा डाका, 500 बोरी गेहूं से भरा ट्रक उड़ा ले गए चोर

**ग्वालियर।**

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गरीबों को बांटने के लिए भेजा गया पांच सौ बोरी गेहूं ट्रक सहित रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। इसकी सूचना से प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी कैमरों के सहारे पुलिस ने जैसे-तैसे खाली ट्रक तो बरामद कर लिया लेकिन उसमें भरकर भेजा गया गेहूं कहाँ गया इसका पता अब तक नहीं लग सका है। गायब हुआ ट्रक थाटीपुर निवासी रंजीत सिंह नामक ट्रक ऑपरेटर का है जिसे राम कुमार गुर्जर नाम का ड्राइवर चलाता है।

राम कुमार का कहना है कि, उसने घाटीगाँव इलाके के रेंहट में स्थित शासकीय वेयरहाउस से गरीबो में बांटने वाला लगभग पांच सौ बोरी गेंहू अपने ट्रक में लोड किया था। इसको विभिन्न कंट्रोल की दुकानों पर वितरित करना था। चालक का कहना है कि वह भरा हुआ ट्रक लेकर पुरानी छावनी पहुंचा और आगरा-मुम्बई हाइवे पर स्थित एक ढाबे के नजदीक रोड के किनारे खड़ा करके वह थोड़ी दूर किसी काम से चला गया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उस जगह पर लौटा तो उसके होश उड़ गए। उसका कहना है कि गेहूं से भरा उसका ट्रक मौके से गायब था।

### थाने पहुंचकर पुलिस को दी सूचना

ड्राइवर ने इस घटना की सूचना पहले अपने मालिक को दी और तत्काल पुरानी छावनी थाने पहुंचकर पुलिस को दी। मामला पीडीएस के गेंहू से जुड़ा था इसलिए थाने से यह सूचना तत्काल वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी गई जिसके चलते हड़कम्प मच गया। पुलिस भी तत्काल एक्शन मोड़ में आ गई। तत्काल आसपास के सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए। एक कैमरे में गायब हुआ ट्रक मुरैना की तरफ जाता दिखा।

### मुरैना के आगे खाली ट्रक खड़ा मिला

सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आगे बढ़ती गई तो गायब हुआ ट्रक मुरैना के आगे चम्बल नदी के पहले टेकरी के पास हाइवे के किनारे खड़ा मिल गया। लेकिन यह पूरी तरह से खाली था। इसमे भरा हुआ पीडीएस का गेंहू पूरी तरह गायब था। पुलिस ट्रक जब्त कर उसे पुरानी छावनी पर ले आई।

एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने बताया कि, ट्रक में भरा पीडीएस का पांच सौ बोरी गेहूं गायब है। जिसकी कीमत लगभग तीन लाख रुपए है। जिस ट्रक में इसे लोड किया गया था उसे तो मुरैना जिले से बरामद कर लिया गया है। अब मुरैना पुलिस की मदद से इसमें भरे गेंहू को चुराकर ले जाने वाले बदमाशो की पतारसी की जा रही है ताकि उन्हें पकड़कर शासकीय गेंहू बरामद किया जा सके। फिलहाल उनका कोई सुराग नहीं लग सका है।

# मोदी के मोहन से मध्य प्रदेश को उम्मीदें...

**माही की गूंज, संजय भटेवरा**

झाबुआ। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के थीम सॉन्ग ''एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी'' को लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया और अब चुनाव में बंपर जीत के बाद ''मोदी के मन में मोहन को मोदी की गारंटी को पूरा करने की जिम्मेदारी है।'' अब मोहन मोदी की गारंटी को कितना पूर्ण कर पाते हैं यह तो समय ही बताएगा। लेकिन मोहन के लिए शिवराज सरकार के कार्यों को जारी रखने के साथ ही उन कार्यों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी है। शिवराज सरकार द्वारा खींची गई लाइन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मोदी के मोहन की है।

भ्रष्टाचार के शिष्टाचार का खात्मा जरूरी

शिवराज सरकार पर कांग्रेस हमेशा ही 50 प्रतिशत कमिशन की सरकार, का आरोप लगाती रही है और शायद इसी कमीशन की सरकार को मोदी ने भाप कर मोदी की गारंटी दी। जिसे आम जनता ने स्वीकार किया और पूरे प्रदेश में मोदी की गारंटी को, 50 प्रतिशत कमीशन और कमलनाथ के वचन के मुकाबले ज्यादा समर्थन मिला और डबल इंजन की सरकार पर अपनी स्वीकृति दी। अब मोहन सरकार के लिए इस ''भ्रष्टाचार के शिष्टाचार'' का खात्मा करना एक बड़ी चुनौती होगी। यही नहीं इस सरकार को शिवराज सरकार के आभामंडल से भी निकलना होगा। शिवराज सरकार पर एक और आरोप कांग्रेस लगाती रही वह है बेलगाम नौकरशाही का जिस पर काबू पाना भी मोहन सरकार के लिए चुनौती होगा।

घोषणावीर के तमगे से मुक्ति पाना भी इस सरकार के लिए आवश्यक होगा। क्योंकि कांग्रेस हमेशा ही शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर कहती रही है और इस सरकार के लिए घोषणावीर के बजट विकास कार्यों को जमीन पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

### पलायन और रोजगार

आदिवासी अंचल झाबुआ-अलीराजपुर के साथ ही कई जिलों में रोजगार के लिए पलायन होना आम बात है और चुनाव में दोनों ही दलों के लिए यह चुनावी मुद्दा रहा है। लेकिन आजादी के अमृतकाल और इतनें चुनाव बीत जाने के बाद भी आज भी यह मुद्दा न केवल जीवित है बल्कि पांव पसारता ही जा रहा है। हर सरकार के रोजगार उपलब्ध कराने के दावे ÷ऊट के मुंह में जीरा÷ वाली कहावत ही चरितार्थ करते नजर आए हैं। झाबुआ-अलीराजपुर जैसे जिले में तो होली के बाद कई गांव खाली हो जाते हैं। यहां ''बाधो रोटा और चालो कोटा'' वाली कहावत आज भी प्रचलित है। जिसका अर्थ है कि, काम की तलाश में कोटा या सूरत जाने से अब तो जिले के श्रमिक अपना श्रम बेचने देश के विभिन्न हिस्सों यहां तक की कर्नाटक और बंगाल जैसे राज्यों में भी जाने लगे है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा रोजगार गारंटी के लिए लाई गई मनरेगा योजना लागू है लेकिन उसमें अनियमित भुगतान तथा कार्य की निरन्तरता न होने से यह योजना अब आमलोगों का विश्वास खोती नजर आ रही है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन होना भी आवश्यक है ताकि आम लोगों का इस योजना के प्रति पूर्ण विश्वास जाग्रत हो।

### कांग्रेस से अपेक्षाएं

लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका के महत्व को भी नज़र अंदाज़ नही किया जा सकता है। इस चुनाव में लोगो ने कॉंग्रेस को विपक्ष की भूमिका के लिए चुना है। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि, वे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका के साथ लोगों का विश्वास जितने का प्रयास करें। विरोध केवल विरोध के लिए न होकर विरोध मुद्दे आधारित होना चाहिए न की व्यक्तिगत विरोध। कांग्रेस यही गलती दोहराती रही है शिवराज सरकार का विरोध करते-करते उसका विरोध केवल शिवराजसिंह चौहान तक की सीमित हो गया था और शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तिगत विरोध को ही सरकार का विरोध मान लिया गया था, जिसको चुनाव में जनता ने नकार दिया। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल वर्तमान में पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, भाजपा ने मोहन यादव को नेतृत्व देकर तो, कांग्रेस ने भी युवा चेहरे जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और हेमंत कटारे के हाथों में कमान सौंप कर इसकी शुरुआत कर दी है। अब दोनों ही दल नए और युवा चेहरों के भरोसे है और आम जनता को भी इन युवा चेहरों से कई उम्मीद् है। मोदी के मोहन से शिवराज के विकास कार्यों को आगे ले जाने की तो, जीतू ,उमंग और हेमंत से उम्मीदें हैं कि, वे कांग्रेस को दिग्विजय और कमलनाथ के आभामंडल से बाहर निकालकर लोकतांत्रिक तरीके से सशक्त विपक्ष की भुमिका का निर्वहन कर सरकार का विरोध करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है। इन युवा चेहरो से आम जनता को भी उम्मीद् है कि, वे न केवल कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे बल्कि सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन भी अच्छे से कर पाएंगे।

# विकास के नाम पर लगाए गए उद्योगों का जनता पर कहरः जमीन,हवा,पानी सभी में जहर ही जहर...

## उद्योगिक क्षेत्र की भूमि, हवा, पानी में जहर पर लगाम के लिए भानु भूरिया का प्रशासन को सात दिन का अल्टीमेटम

**माही की गूंज, मेघनगर। इमरान शेख**

अंतरवेलिया नाले में मेघनगर इंडस्ट्रियल एरिया के बहने वाले एसिड युक्त जहरीला पानी पीने से नील गाय के मरने के बाद ग्रामीणों द्वारा चक्काजाम किया गया। जिसके बाद जागे भाजपा नेता भानु भूरिया ने भी मेघनगर के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित हो रहे केमिकल सहित अन्य कारखानों से निकलने वाले जहरीले पानी की हकीकत को जमीन पर उतरकर देखा। जिसमें उनके साथ आसपास के क्षेत्रों के कई ग्रामीणों सहित मेघनगर अनुविभागीय अधिकारी मुकेश सोनी ,तहसीलदार विजेंद्र कटारे, जनपद सदस्य धनसिंह भूरिया मौजूद थे। जिसके पानी में मिले एसिडिक जहर को देखने के बाद मौके पर ही राठौर फार्मा ,ट्रेंट केमिकल ,ब्रह्मोस केमिकल,मेघनगर ऑर्गेनिक,विनी इंटरप्राइजेज,अंकित इंटरप्राइजेज के विरुद्ध पंचनामा बनाया जाकर इन फैक्ट्रियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत नोटिस दिए गए है। साथ ही प्रशासन को भानु भूरिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि, सात दिन में इन कारखानों से होने वाले प्रदूषण को नही रोका गया तो पूरे जिले की टीम को लाकर वो औद्योगिक क्षेत्र का घेराव करेंगे।

### पहले भी हो चुके हैं इस औद्योगिक जहर के विरुद्ध कई आंदोलन

मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित खाद,ब्रोमिन, मेगनीज, केमिकल और टायर प्लांट सहित लगभग सभी कारखानो के प्रदूषण के विरुद्ध कांग्रेस के बचपन बचाओ आंदोलन से लेकर, हिंदू युवा वाहिनी, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन सहित आम जनता ने कई बड़े आंदोलन किए। मगर फिर भी ये सभी उद्योग जो पर्यावरण संरक्षण कानून 1986,जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)अधिनियम) 1974,वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण)अधिनियम 1981के अंतर्गत मिलने वाली अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सभी शर्तों का उल्लंघन करते हुए दिन-रात बेखौफ संचालित हो रहे हैं। वही मेघनगर ,अंतरवेलिया,अगराल सहित आसपास के गावों के लाखो लोगों को ये हवा और पानी के माध्यम से धीमा जहर बांट रहें हैं। इन कारखानों ने भूजल इतना दूषित कर दिया है की आसपास के 5 किलोमटर के क्षेत्र में हैंडपंपों ,बोरिंग से लाल जहरीला पानी आ रहा है। और तो और गारिया नाले से होता हुआ ये प्रदूषित एसिड युक्त पानी मेघनगर को मिली 32 करोड़ के नल जल योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच चुका है। मगर हवा ,पानी, जमीन में जहर फैला रहे जहर के इन सप्लायरों के विरुद्ध आज तक कोई ठोस और निर्णायक कारवाई नही हुई। जहर के इन सप्लायरों की सांठगंठ इतनी तगड़ी है की संविधान के अनुच्छेद 21 में मानव को दिए गए स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार भी स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के लिए कोई मायने नही रख रहा। पूरे क्षेत्र के लोग इस दूषित पानी को पीने से केंसर,किडनी और चमड़ी के रोगों से ग्रसित हो चुके हैं। साथ ही हवा में उड़ते जहर से भी क्षेत्र के लोग अस्थमा,कंजक्टिवाइटिस सहित कई गंभीर बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया हैं। प्रभावित इस पूरे क्षेत्र के लोगों का पानी पीना,सांस लेना सब दुर्भर हो चुका है और स्वस्थ जीवन का संवैधानिक अधिकार भी यहां के लोगों के लिए सिर्फ एक किताबी जुमला बन कर रह गया है।

### कार्रवाई शून्यः हर बार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने,नमूने लेने,नोटिस देने की चलती है नोटंकी

प्रशासन द्वारा सिर्फ 6 फैक्ट्रियों को ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के नोटिस दिए गए जबकि आद्योगिक क्षेत्र में स्थित 90 प्रतिशत उद्योग पर्यावरण कानूनों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए जल,जमीन और हवा को दूषित कर रहें हैं। मगर प्रशासन सिर्फ छोटी मछलियों का शिकार गरीब की जोरू सबकी भाभी (कमोजर पर सब अधिकार जताते है) की तर्ज पर खाना पूर्ति करने के लिए कर रहा है। हर बार प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के अधिकारी जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम 1974 की धारा 21 के अंतर्गत नमूने तो संग्रहित करते हैं मगर इसी अधियम की धारा 22 के अंतर्गत नमूने के परिणामो का उपयोग अपने आर्थिक हित साधने में करने लग जाते हैं। जबकि इस अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत इन समस्त उद्योगों को धारा 25 के अंतर्गत प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के अधिकार का इस्तेमाल कभी नही किया गया। ना ही कभी क्षेत्र के एयर क्वालिटी इंडेक्स की जांच की जो की पूरा दूषित हो चुका है। पूर्व में भी स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में कई बार नोटिस इन प्रदूषण करने वाले उद्योगों को दिए गए। बदले में उन उद्योगों द्वारा भविष्य में ऐसा ना किए जाने का हलफनामा दे दिया जाता है। साथ ही अधिकारियों द्वारा आर्थिक सांठगांठ कर स्वीकार कर लिया जाता है और अगले दिन से फिर जहर की ये दुकानें बेखौफ संचालित होने लग जाती है, इसी तरह निरीक्षण, नमूने,नोटिस की ये नौटंकी बरसों से बदस्तूर जारी है ।

### सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी कर रहें हैं अवमानना

दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने पर रोक वाले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हम लोगों को मरता हुआ नही छोड़ सकते वायु प्रदूषण को तुरंत रोका जाए। साथ ही साथ ही नदियों के जल प्रदूषण पर लिए स्वतः संज्ञान वाले आदेश में सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों एसए बोबडे, एएस बोपन्ना और वी.रामासुब्रमणियम ने साफ कहा था, प्रदूषण मुक्त जल और साफ पर्यावरण नागरिकों का मालिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। साथ ही कहा था संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 47,48 के अंतर्गत जन स्वास्थ्य को ठीक करना और पर्यावरण सरक्षण करना राज्य का दायित्व है। मगर खुलेआम जल,जमीन,वायु को दूषित कर पर्यावरण प्रदूषण कर रहे। मेघनगर के इन ज़हरीली उद्योगों के खिलाफ कारवाई ना करके सभी जिम्मेदार अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी खुलेआम अवमानना कर रहे हैं। जबकि पर्यावरण जल ,वायु और वायु सरक्षणर कानून की कई धाराएं इनकी शर्तों का उल्लंघन करने पर किसी भी इकाई की अनापत्ति रद्द करने और इकाई को स्थाई रूप से बंद करने के अधिकार प्रदूषण बोर्ड को और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान स्थानीय प्रशासन को देते है। अब देखना ये है की कोई ठोस और निर्णायक कारवाई होती है या वही ढाक की तीन पात की स्थिति रहेगी।

# पुण्यतिथि पर मामा बालेश्वर दयाल को भारत रत्न देने की मांग

## आज भी पहचान को तरसता मामाजी का आश्रम और समाधि स्थल

**माही की गूंज बामनिया, गौरव भण्डारी**

समाजवादी चिंतक और पूर्व राज्यसभा सांसद स्व.मामा बालेश्वर दयाल की 25 वी पुण्यतिथि 26 दिसम्बर मंगलवार को उनकी कर्म स्थली बामनिया में मनाई जाएगी। 25 साल पहले आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासीयो के विकास और उनके सामाजिक सुधार के कार्य करने वाले मामाजी दुनिया से विदा हो गए थे, लेकिन उनके निधन के बाद से लगातार उनके बामनिया स्थित आश्रम पर उनके अनुयायो का ऐसा जमावड़ा लगना शुरू हुआ कि, आज 25 वर्ष बाद इस स्थान पर मेला लगना शुरू हो गया और हजारो की संख्या में लोगो की भीड़ जुटना शुरू हो गई जो आज भी सतत् रूप से जारी है और यहां आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मामा बालेश्वर दयाल के शिष्यों में देश की राजनीति में बड़ी बुलंदी हासिल करने वाले नेताओं के नाम शामिल हैं और वो मामा जी के निधन के बाद यहां आते रहे हैं। पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नाडीज, उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रदेश की पूर्व उपमुख्यमंत्री जमनादेवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, भाजपा नेता दिलीप सिंह भूरिया सहित कई बड़ी नामचीन हस्तियां मामा जी के जाने के बाद आते-जाते रहे हैं।

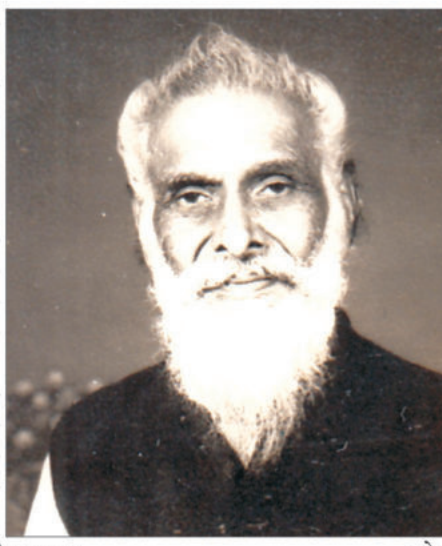

### 25 वीं पुण्यतिथि पर उमड़ेगा भक्तों का सैलाब

26 दिसम्बर को मामा बालेश्वर दयाल के 25 वे पुण्य स्मरण पर भक्तों का भारी सैलाब उमड़ेगा। यहां बामनिया स्थित मामा जी आश्रम पर मामा जी के भक्त एक दिन पहले से बामनिया पहुँचने शुरू हो जाते हैं। सबसे अधिक लोग राजस्थान के बांसवाड़ा ओर डूंगरपुर जिले के आदिवासी अंचल के लोग आते हैं। जहां आज भी मामा जी को भगवान की तरह पूजा जाता है। यहां के आदिवासी निस्वार्थ भाव से पैदल यात्रा कर मामाजी के भजनों को गाते गुनगुनाते पहुचते है। राजस्थान के अलावा मध्यप्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम जिले के सैलाना क्षेत्र और गुजरात के दाहोद व पंचमहल जिले से भी बड़ी संख्या में आदिवासी अंचल के ग्रामीण मामा जी समाधि पर पहुँचते है।

### भारत रत्न देने की उठी मांग

जिस तरह से मामाजी आदिवासी अंचल में फैली कुरीतियों को समाप्त कर आदिवासीयो के उत्थान के लिए कार्य किया है। अब उनके लिए भारत रत्न दिए जाने की मांग उठने लगी है। मामा जी की पुण्यतिथि पर लगभग 20 से 25 हजार लोग दो दिन में उनके समाधि स्थल पर पहुँच कर उनमें अपनी आस्था और समाज के लिए किए कार्यो का जीवंत उदाहरण पेश करते हैं। जनता दल यू के नेता पर मामा जी शिष्य हरिओम सूर्यवंशी ने बताया कि, इस बार मामा जी की 25 वी पुण्यतिथि है और इस पर विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। देश मे रही सरकारे मामा जी को उपेशित कर रही है। इस बार हम सभी मामाजी को भारत रत्न दिए जाने की मांग करेगे।

### अनदेखी का शिकार मामाजी का आश्रम

मामा जी के निधन के बाद से बदहाली का शिकार हुआ उनका आश्रम आज भी उसी उपेक्षा का शिकार हो रहा है। स्थानीय प्रशासन और मध्यप्रदेश की सरकार की ओर से मामाजी के आश्रम ओर समाधि स्थल पर किसी प्रकार का विकास नही किया है। लगातार उनके आश्रम ओर समाधि स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की जाती रही है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नही हो पाई है। मामाजी का कर्म क्षेत्र राजस्थान और गुजरात के हिस्से में अधिक होने से यहां आने वाले लोगो की संख्या भी उसी क्षेत्र के लोगो की होने से स्थानीय राजनीति भी इस स्थान को बड़ा बनाने के लिए कोई पहल नही करते। यहां आने वाले भक्तों के लिए रहने, खाने तक की व्यवस्था नही है और हजारो भक्त पूरी रात खुले में भारी ठंड के बावजूद ठिठुरते भजन करते हुए मामाजी को याद करते हैं। पुरषों के साथ-साथ बड़ी संख्या में महिलाये ओर बच्चे भी यहां पहुच कर मामा को प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं ।

# यह कैसी शिक्षा व्यवस्थाः जहां नियम का ही पालन न हो

**माही की गूंज, झाबुआ।**

*शिक्षा का अर्थ ही है कि अच्छा ज्ञान और अच्छा ज्ञान हमेशा ही नियम पालन की अवधारणा पर आधारित है। सूर्य और चंद्रमा अपने नियमबद्धता के चलते ही पूजनीय है और नियम से चलने वाली हर चीज अनुकरणीय है। जहां नियम है वहा विश्वास अपने आप बढ़ता चला जाता है, लेकिन दूसरों को शिक्षा देने वाले खुद ही अपने ही बनाए नियम का पालन नहीं करेंगे तो इसे आप क्या कहेंगे....?*

वह भी शिक्षा विभाग जैसे आम जनता से जुड़े विभाग में जो देश की भावी पीढ़ी को तैयार करता है और यही पीढ़ी आगे चलकर देश को चलाएगी।

हम बात कर रहे जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत आने वाले छात्रावास के अधीक्षकों की नियुक्ति संबंधी आदेश की। जिसमें नियमों को ताक में रखकर आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और मलाईदार पद पर अपने चहेतो की मनमाने तरीके से नियुक्ति की जा कर भ्रष्टाचार के रूप में छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक की जेबे भरी जा रही है।

जनजातिय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावास, आश्रम में अधीक्षक की नियुक्ति के संबंध में सामान्य नियम है कि, इस पद पर यथासंभव उच्च माध्यमिक शिक्षक के समकक्ष पद पर कार्यरत कर्मचारी को छात्रावास अधीक्षक का कार्य सोपा जा सकता है। यही नहीं छात्रावास अधीक्षक के पद पर कोई भी कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक समय तक लगातार कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन जिले के अधिकांश छात्रावासों में इन दोनों नियमों को ताक में रखकर मनमाने तरीके से न केवल नियुक्तिया की गई है, बल्कि अधिकांश छात्रवासो में कई अधीक्षक लंबे समय से अंगद के पांव की तरह जमे हुए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता को सूचना के अधिकार के तहत 23 नवंबर 2023 को प्राप्त हुई जानकारी में अधिकांश जगह शासन के द्वारा तय नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है यह स्पष्ट रूप से सामने आया।

आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जिले में समस्त छात्रावासों में पदस्थ अधीक्षकों की जानकारी मांगी तो, देश के भविष्य विद्यार्थियों को ज्ञान देने वाले शिक्षक व अधिकारी ही सारे नियमों को ताक में रख उक्त पदों पर मनमानी सामने आई है। कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग भोपाल द्वारा छात्रावासो में की जा रही भर्ती की अनियमितताओं की शिकायतों पर पत्र क्रमांक 164/23255 13 सितंबर 2017 को जारी आदेश में भी उल्लेख किया गया कि, संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावास, आश्रमों में पूर्णकालिक अधीक्षको, संविदा शिक्षक, अधीक्षक के पद पर शिक्षकों की पद स्थापना किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए है। परंतु आप के द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है पत्र में दर्शाया गया है।

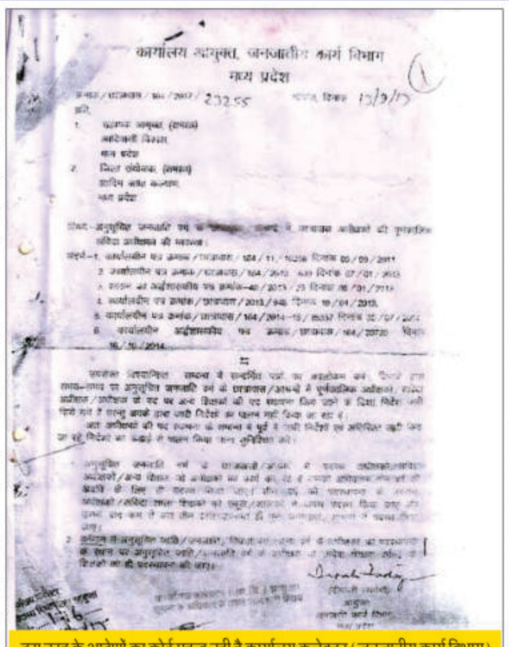

इस तरह के आदेशों का कोई महत्व नही है कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) झाबुआ को, इसलिए आदेषो को ताक में रख कर रहे अपनी मनमानी।

साथ ही आदेश में लिखा गया कि, अधीक्षकों की पद स्थापना के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों एवं अतिरिक्त जारी किए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। आदेश में उल्लेख किया गया कि, उच्च माध्यमिक स्तर, सविदा शिक्षक वर्ग-2 के शिक्षकों की छात्रावास, आश्रम में अधीक्षक पद हेतु अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए पदस्थ किया जाए। तीन वर्ष की पदस्थापना के उपरांत अधीक्षकों को पुनः अपने स्कूल शालाओं में पदस्थ किया जाए और उसके बाद कम से कम तीन वर्ष के बाद ही उक्त शिक्षक की पदस्थापना अधीक्षक के रूप में किया जा सकता है आदेश जारी हुए। लेकिन झाबुआ जिले में ऐसे आदेशों का कोई महत्व नहीं है यह देखा जा सकता है।

23 नवंबर 2020 से 23 नवंबर 2023 तक के मध्य इन तीन वर्षों में पदस्थ अधीक्षक 55 के करीब है जिसमें 40 से अधिक प्राथमिक स्तर के शिक्षक संविदा वर्ग 1 या फिर सहायक शिक्षक की पदस्थापना की गई है।

वहीं तीन वर्ष से अधिक जिसमें एक ही स्थान पर ऐसे भी कई छात्रावास है जिसमें सारे नियमों व आदेशों को ताक में रख 3 वर्ष से अधिक समय से लेकर 15 से 20 वर्ष के मध्य तक छात्रावासों में अधीक्षक के रूप में पदस्थ है। वहीं सूचना अधिकार में प्राप्त जानकारी में 12 ऐसे शिक्षकों की पदस्थापना है जिसमें आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री या प्रभारी मंत्री के आदेश पर जनजाति कार्यालय झाबुआ ने आदेश जारी किया। जिसमें अधीक्षकों को पदस्थ किया गया जो तीन वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक छात्रावास के अधीक्षक पदों पर जमे हुए हैं। उक्त आदेशों में भी प्राथमिक स्तर के शिक्षक, अधीक्षक पद पर पदस्थ है।

वहीं इसके अलावा भी 65 से अधिक ऐसे शिक्षक है जो तीन वर्ष से लेकर 15 से 20 वर्ष के मध्य तक अपने पद पर आसीन है। जिसमें भी गिनती के ही माध्यमिक स्तर, वर्ग 2 के या उच्च शिक्षक पदस्थ है। बाकी प्राथमिक स्तर के ही शिक्षक वर्ग एक, सहायक शिक्षकों को नियम के विरुद्ध अधीक्षकों के पद पर स्थापित कर रखे हैं। ऐसे में दूसरों को शिक्षा देने वाले शिक्षक व संबंधित विभाग खुद ही अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा...? यह समझा जा सकता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422